राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक

क्रांति समय

कार्यालय ऑफिस

क्रांति समय दैनिक समाचार में
प्रेसनोट, नोटिस, वेपार संबंधित संपर्क करें
पता:- एस.टी.पी.आई-सुरत-395023
संपर्क नं.-7490923915
ईमेल:-info.krantisamay@gmail.com

सुरत गुजरात से प्रकाशित, मुंबई, उत्तरप्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्यप्रदेश, उत्तरांचल, उत्तराखंड, दिल्ली, हरियाणा में प्रकाशित

सुरत-गुजरात, संस्करण शनिवार 17 जनवरी 2026 वर्ष-8,अंक-321 पृष्ठ-08 मूल्य-01 रूपये

Website : www.krantisamay.com & epaper.krantisamay.com www.facebook.com/krantisamay1 www.twitter.com/krantisamay1

महाराष्ट्र निकाय चुनाव में बीजेपी की बंपर जीत

● 29 में 23 नगर निगमों में बीजेपी और सहयोगियों का कब्जा ● मुंबई-नागपुर-पुणे सभी बड़े शहर फतह, लातूर-चंद्रपुर में कांग्रेस को बहुमत

मुंबई (एजेंसी)। महाराष्ट्र के नगर निगम चुनाव में भाजपा गठबंधन को एकतरफा जीत मिली है। 29 नगर निगमों में से 23 में भाजपा गठबंधन को जीत मिली है। मुंबई के बृहन्मुंबई नगर निगम में भाजपा+शिवसेना (शिंदे) अलायंस कुल 227 सीटों में से 118 सीटों पर जीत दर्ज की है। इसके अलावा नागपुर, पुणे, ठाणे, नवी मुंबई, पिंपड़ी चिड़वाड और नासिक में भी भाजपा गठबंधन जीत रहा है। लातूर और चंद्रपुर में कांग्रेस को जीत मिली है। परभणी नगर निगम में शिवसेना (उद्धव) को बढ़त है। वसई विरार में बहुजन विकास अघाड़ी और मालेगांव में शिवसेना (शिंदे) आगे चल रही है। शुक्रवार को नगर निगम चुनाव की सुबह 10 से काउंटिंग शुरू हुई। राज्य में निगम चुनाव के लिए 15 जनवरी को वोटिंग हुई थी। 893 वार्डों में कुल 15,931 उम्मीदवार मैदान में हैं। नगर निगम की कुल 2869 सीटें हैं। इनमें से 68 उम्मीदवार निर्विरोध जीत चुके हैं।

तरुण चुघ बोले- महाराष्ट्र की जनता ने पीएम मोदी को आशीर्वाद दिया

महाराष्ट्र नगर निगम चुनाव पर बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुघ ने कहा- आज जश्न का दिन है। महाराष्ट्र में सभी नगर समितियों और नगर निगमों के लोगों ने पीएम मोदी की नीतियों, उनके राष्ट्रवाद और विकसित भारत के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को आशीर्वाद दिया है। उन्होंने कहा कि यह जीत साफ दिखाती है कि लोग पाकिस्तान की सेना के धुन पर नाचने वालों को अपने वोटों से सबक सिखा रहे हैं। यह नतीजा राष्ट्रवादी ताकतों की जीत है। महाराष्ट्र नगर निगम चुनाव में भाजपा गठबंधन को मिली बढ़त पर भाजपा नेता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि- आप सभी ने देखा कि आज बीजेपी गठबंधन ने बीएमसी चुनावों में शानदार जीत हासिल की है। यह दिखाता है कि पीएम मोदी के नेतृत्व में बीजेपी और एनडीए की स्वीकार्यता लगातार बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि हाल ही में हमने केरल नगर निगम चुनावों में तिरुवनंतपुरम में पहली बार बहुमत हासिल किया।

मुंबई में नवाब ने बनाया फकीर!

मुंबई बीएमसी चुनावों में अजित पवार ने पार्टी के दिग्गज नेता नवाब मलिक को कमान सौंपी थी। इसी वजह से उनकी बीजेपी से तनातनी बढ़ी थी लेकिन अकेले चुनाव लड़ने का फैसला भारी पड़ा। मुंबई में किंगमेकर बनने का दावा कर रहे नवाब मलिक की अगुवाई में पार्टी एनसीपी तीस सीटों के टारगेट के सामने सिर्फ गिनती की सीटें ही जीत पाई। नवाब मलिक के भाई भी चुनाव हार गए।

अजित पवार के दोनों गढ़ में खिला कमल

महाराष्ट्र में मुंबई से लेकर पश्चिम महाराष्ट्र तक बीजेपी की लहर सामने आई है। राज्य में बीजेपी की अगुवाई वाली महायुति सरकार में डिप्टी सीएम अजित पवार को इन चुनावों में तगड़ा झटका लगा है। अजित पवार की पार्टी ने महायुति को छोड़कर मुंबई में जहां अकेले चुनाव लड़ा था तो वहीं पार्टी ने अपने मजबूत गढ़ पुणे, पिंपरी चिंचवड में वापसी के लिए चाचा (शरद पवार) की अगुवाई वाली एनसीपी से हाथ मिलाया था।

इसके बाद सुप्रिया सुले और अजित पवार एक मंच पर सामने आए थे। शरद पवार गुट के विधायक रोहित पवार ने भी पुणे और पिंपरी चिंचवड में खूब चुनाव प्रचार किया था, लेकिन चुनाव नतीजों में दोनों स्थानों पर बीजेपी सत्ता हासिल करने में सफल रही है। पुणे में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है तो वहीं दूसरी एनसीपी का प्रदर्शन काफी कमजोर रहा है।

इंदौर में राहुल की मीटिंग को नहीं मिली मंजूरी

अब सिर्फ बॉम्बे हॉस्पिटल और भागीरथपुरा ही जाएंगे

भोपाल (एजेंसी)। इंदौर के भागीरथपुरा क्षेत्र में दूषित पानी के कारण अब तक 24 लोगों की मौत के बाद हालात का जायजा लेने कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी शनिवार 17 जनवरी को इंदौर आ रहे हैं। हालांकि, इस दौरान इंदौर में कांग्रेस नेताओं और नगरीय जनप्रतिनिधियों के साथ प्रस्तावित बैठक को प्रशासन से अनुमति नहीं मिल पाई है। कांग्रेस ने प्रदेशभर के पार्षदों, महापौरों, नगर पालिका और नगर परिषद अध्यक्षों व उपाध्यक्षों के साथ राहुल गांधी की बैठक के लिए अभय प्रशाल और आनंद मोहन माथुर सभागार में कार्यक्रम प्रस्तावित किया था।

इसके लिए करीब एक हजार लोगों की मौजूदगी की अनुमति मांगी गई थी, लेकिन जिला प्रशासन ने बैठक को मंजूरी नहीं दी। कांग्रेस के संगठन प्रभारी डॉ. संजय कामले ने बताया कि प्रशासन से अनुमति नहीं मिलने के कारण बैठक को रद्द करना पड़ा है। अब राहुल गांधी का इंदौर दौरा सीमित कार्यक्रम तक ही रहेगा।

गालीबाजी, लुंगी-पुंगी, कुछ नहीं आया काम

नफरती पॉलिटिक्स के 'हीरो' राज ठाकरे की राजनीति खत्म?

मुंबई (एजेंसी)। महाराष्ट्र निकाय चुनाव 2026 के नतीजे आ गए हैं। बीजेपी ने विधानसभा चुनाव की तरह ही प्रचंड जीत हासिल की है। इस जीत के साथ ही महाराष्ट्र की राजनीति को नया संदेश गया है। नफरती पॉलिटिक्स हीरो रहे राज ठाकरे निकाय चुनाव में खत्म हो गए हैं। मनसे मुंबई महानगरपालिका में तीन से चार सीटें जीतती दिख रही है। मराठी अस्मिता के नाम पर गालीबाजी और लुंगी-पुंगी करने वाले राज ठाकरे के नफरती पॉलिटिक्स को महाराष्ट्र की जनता ने पूरी तरह से खारिज कर दिया है। उनके चक्कर में उद्धव ठाकरे के हाथ भी जल गए हैं। बीएमसी की सत्ता 30 साल बात उद्धव ठाकरे के हाथों से जा रही है। मनसे प्रमुख राज ठाकरे की पहचान महाराष्ट्र की राजनीति में नफरती पॉलिटिक्स को लेकर ही रही है। मराठी अस्मिता के नाम पर गैर मराठियों के साथ मारपीट और गालीगलौज उनके कार्यकर्ताओं की पहचान रही। राजे ठाकरे अपनी सभाओं में खुद भी जुबान पर कंट्रोल नहीं कर पाते थे। निकाय चुनाव में प्रचार के दौरान कहा था कि यूपी-बिहार के लोगों को समझना चाहिए कि हिंदी आपकी भाषा नहीं है। मुझे भाषा से नफरत नहीं है। लेकिन अगर आप इसे थोपेंगे तो मैं लात मारूंगा। राज ठाकरे यही नहीं रुके थे। उन्होंने कहा था कि वो चारों तरफ से महाराष्ट्र आ रहे हैं और आपका हिस्सा छीन रहे हैं। भाषा चली गई तो आप खत्म हो जाएंगे।

अब सिर्फ पीड़ित परिवारों से मुलाकात करेंगे राहुल

राहुल गांधी इंदौर पहुंचने के बाद पहले बॉम्बे हॉस्पिटल जाएंगे, जहां वे दूषित पानी से बीमार हुए मरीजों और उनके परिजन से मुलाकात करेंगे। इसके बाद वे भागीरथपुरा पहुंचकर उन परिवारों से मिलेंगे, जिनके परिजनों की दूषित जल के कारण मौत हुई है। राहुल गांधी के दौरे को लेकर जिला प्रशासन अलर्ट मोड में है। मध्यप्रदेश कांग्रेस कमेटी ने 17 से 31 जनवरी 2026 तक आंदोलन की घोषणा की है। यह आंदोलन मनरेगा में बदलाव कर कानूनी अधिकारों की बहाली, इंदौर के भागीरथपुरा में दूषित पानी से हुई मौतों और प्रदेश में बिगड़ती जल गुणवत्ता के विरोध में किया जाएगा। आंदोलन का पहला चरण 17 जनवरी को होगा। इस दिन शहरी जिला कांग्रेस कमेटियां भागीरथपुरा की घटना और जल गुणवत्ता के मुद्दे पर जिला स्तर पर एक दिवसीय उपवास रखेंगी। यह उपवास सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक रहेगा।

वेनेजुएलाई नेता ने अपना नोबेल पुरस्कार ट्रम्प को दिया

● मचाडो के प्रेसीडेंट बनने की चर्चा थी, लेकिन ट्रम्प का समर्थन नहीं

वॉशिंगटन (एजेंसी)। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प ने गुरुवार को व्हाइट हाउस में वेनेजुएला की विपक्षी नेता मारिया कोरिना मचाडो से मुलाकात की। वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को अगवा करने के बाद यह उनकी किसी भी वेनेजुएलाई नेता से पहली आमने-सामने की मुलाकात थी। मुलाकात के बाद माचाडो ने कहा कि उन्होंने ट्रम्प को नोबेल शांति पुरस्कार का मेडल भेंट किया है। उन्होंने कहा, 'मुझे लगता है कि आज हम वेनेजुएलावासियों के लिए एक ऐतिहासिक दिन है।' बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत में मचाडो ने ट्रम्प को अपना पुरस्कार सौंपने के बारे में बताया, लेकिन उन्होंने दूसरी कोई जानकारी नहीं दी। वहीं, व्हाइट हाउस ने भी यह नहीं बताया कि ट्रम्प ने मेडल स्वीकार किया या नहीं। व्हाइट हाउस छोड़ने के बाद मचाडो ने बाहर जुटे समर्थकों से स्पेनिश में कहा, हम राष्ट्रपति ट्रम्प पर भरोसा कर सकते हैं। हालांकि, ट्रम्प ने माचाडो को नई नेता के रूप में समर्थन नहीं दिया है।

वॉशिंगटन के उत्तराधिकारी को मेडल लौटाया:मचाडो

मचाडो ने ट्रम्प को नोबेल पुरस्कार देते हुए 1825 में अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के हीरो मार्क्विस डे लाफायेट का उदाहरण दिया।
उन्होंने कहा, 200 साल पहले मार्क्विस डे लाफायेट ने जॉर्ज वॉशिंगटन की तस्वीर वाला मेडल साइमन बोलिवर को दिया था, जो अमेरिका और वेनेजुएला के बीच स्वतंत्रता की लड़ाई में भाईचारे का प्रतीक था। अब, बोलिवर के लोगों ने वॉशिंगटन के उत्तराधिकारी (ट्रम्प) को नोबेल मेडल लौटाया है। लाफायेट ने दक्षिण अमेरिका के आजादी के नेता साइमन बोलिवर को एक खास सोने का पदक भेजा। इस पदक पर अमेरिका के पहले राष्ट्रपति जॉर्ज वॉशिंगटन की तस्वीर बनी हुई थी।
यह तोहफा दोनों देशों के बीच भाईचारे और तानाशाही के खिलाफ साझा लड़ाई का प्रतीक था। बोलिवर ने इस पदक को बहुत सम्मान दिया और इसे हमेशा पहनते रहे।

रिस्क लेने वालों को अब रिस्पेक्ट मिलती है

पीएम बोले-10 साल पहले देश में 500 से भी कम स्टार्टअप थे, आज ये संख्या 2 लाख से ज्यादा

नई दिल्ली (एजेंसी)। नेशनल स्टार्टअप डे के अवसर पर पीएम मोदी ने कहा कि 10 साल पहले देश में 500 से भी कम स्टार्टअप थे, आज ये संख्या बढ़कर 2 लाख से ज्यादा हो गई है। उन्होंने बताया कि बीते दशकों में हमने डिजिटल स्टार्टअप्स और सर्विस सेक्टर में काफी शानदार काम किया है। अब समय है कि हमारे स्टार्टअप्स मैन्युफैक्चरिंग पर और ज्यादा ध्यान दें। हमें नए प्रोडक्ट्स बनाने होंगे। पीएम मोदी ने कहा कि हमें दुनिया के बेस्ट क्वालिटी के प्रोडक्ट्स बनाने होंगे। टेक्नोलॉजी में भी यूनिक आइडियाज पर काम करके लीड लेनी होगी। भविष्य इसी का है। मैं आपको भरोसा देता हूं, आपके हर प्रयास में सरकार आपके साथ खड़ी है। स्टार्टअप इंडिया केवल एक स्कीम नहीं, बल्कि एक रेनबो विजन है। ये अलग-अलग सेक्टर्स को नई अपॉर्चुनिटी से जोड़ने का जरिया है। रिस्क-टेकिंग पर मैं जोर देता रहा हूं, क्योंकि ये मेरी भी पुरानी आदत है। जो काम कोई करने को तैयार नहीं होता, जिन कामों को दशकों से पहले की सरकारों ने नहीं छुआ, क्योंकि उनमें चुनाव हारने और कुर्सी जाने का डर था। मैं उन कार्यों को अपना दायित्व समझकर जरूर करता हूं। आपकी तरह ही मेरी भी मानना है कि जो काम देश के लिए जरूरी है, वो काम किसी न किसी को तो करना ही होगा। किसी को तो रिस्क लेना ही होगा। नुकसान होगा तो मेरा होगा और अगर फायदा होगा तो मेरे देशवासियों को मिलेगा।

● **आज रिस्क-टेकिंग, मैनस्ट्रीम बन चुका है-** आज रिस्क-टेकिंग, मैनस्ट्रीम बन चुका है। मंथली सैलरी से आगे सोचने वालों को अब केवल एक्सेप्ट ही नहीं किया जाता, उन्हें अब रिस्पेक्ट किया जाता है। जिन रिस्क-टेकिंग आइडियाज को पहले लोग फ्रींज मानते थे, वो अब फेशन बन रहे हैं। 10 साल पहले देश में 500 से भी कम स्टार्टअप थे, आज ये संख्या बढ़कर दो लाख से ज्यादा हो गई है। 2014 में भारत में सिर्फ 4 यूनिकॉर्न थे, आज भारत में करीब सवा सौ सक्रिय यूनिकॉर्न हैं। दुनिया भी आज इस सक्सेस स्टोरी को हैरानी से देख रही है। आने वाले समय में जब भारत की सक्सेस स्टोरी की बात होगी, तब यहां बैठे कितने ही युवा खुद में एक ब्राइट केस स्टडी बनने वाले हैं।

यह कितने ही सपनों के साकार होने की यात्रा

ये कितने ही सपनों के साकार होने की यात्रा है। आज से 10 साल पहले, विज्ञान भवन में 500-700 नौजवानों के बीच इस कार्यक्रम की शुरुआत की थी। उस समय स्टार्टअप की दुनिया में जो नए-नए लोग आ रहे थे, उनके अनुभव मैं सुन रहा था और मुझे याद है एक बेटी, जो कॉरपोरेट वर्ल्ड से अपनी नौकरी छोड़कर स्टार्टअप की तरफ जा रही थी। नौकरी छोड़कर वो कोलकाता अपनी मां से मिलने गई और मां से कहा कि मैंने नौकरी छोड़ दी है और मैं स्टार्ट करना चाहती हूं। फिर उसकी मां ने कहा, सर्वनाश-तुम बर्बादी की राह पर क्यों जा रही हो। स्टार्टअप को लेकर ये सोच हमारे देश में थी और आज हम कहां से कहां पहुंच गए, विज्ञान भवन से भारत मंडपम तक, जहां जगह नहीं है। नेशनल स्टार्टअप डे का ये अवसर, स्टार्टअप फाउंडर्स और इनोवेटर्स का ये समूह, मैं अपने सामने नए और विकसित होते भारत का भविष्य देख रहा हूं।

नितिन नवीन के भाजपा अध्यक्ष बनने की आ गई तारीख

पार्टी ने जारी किया पूरा शेड्यूल 20 जनवरी को होगी घोषणा

नई दिल्ली (एजेंसी)। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव की तारीख की घोषणा हो गई है। पार्टी ने बताया है कि निर्वाचन की प्रक्रिया 19 जनवरी से शुरू होकर 20 जनवरी 2026 तक पूरी होगी। बीजेपी ने शुक्रवार को पार्टी के अध्यक्ष पद के चुनाव का विस्तृत शेड्यूल भी जारी किया है।

इससे पहले बिहार के पांच बार के विधायक को बीते 14 दिसंबर को भाजपा का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। अब चुनाव के तारीखों के बाद उनके निर्विरोध चुने जाने की संभावना है क्योंकि पार्टी के किसी अन्य नेता की दावेदारी की संभावना नहीं के बराबर है। पार्टी ने राष्ट्रीय निर्वाचन अधिकारी और राज्यसभा सांसद के लक्ष्मण द्वारा जारी किए गए चुनाव शेड्यूल के मुताबिक भाजपा चीफ के चुनाव के लिए नॉमिनेशन 19 जनवरी को दोपहर 2 बजे से 4 बजे के बीच भरे जा सकते हैं और उम्मीदवार उसी दिन शाम 5 बजे से 6 बजे के बीच अपना नॉमिनेशन वापस ले सकते हैं। उम्मीदवारों के नामांकन पत्र के साथ दस्तावेजों की जांच 19 जनवरी को शाम 4 बजे से 5 बजे के बीच की जाएगी। लक्ष्मण ने कहा है कि अगर जरूरत पड़ी तो 20 जनवरी को वोटिंग होगी और उसी दिन नए चुने गए भाजपा अध्यक्ष के नाम की आधिकारिक घोषणा की जाएगी। चुनाव प्रक्रिया पार्टी हेडक्वार्टर में ही होगी। पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधायक दिवंगत नवीन किशोर प्रसाद सिन्हा के बेटे नितिन नवीन एक तेज-तर्रार, वैचारिक रूप से दृढ़ और संगठन के प्रति गहरी प्रतिबद्धता रखने वाले व्यक्ति के रूप में जाने जाते हैं।

डीआरजी दंपति समेत 40 मकानों पर चला बुलडोजर

● 35 और टूटेंगे, बीजापुर में रोते-रोते लोगों ने छोड़ा अपना घर ● बोले-प्रशासन घर तोड़ रहा, गांव जाएंगे तो नक्सली मार देंगे

बीजापुर (एजेंसी)। बीजापुर में न्यू बस स्टैंड के पीछे अब तक 40 अवैध मकान ढहाए जा चुके हैं और कार्रवाई लगातार जारी है। इस दौरान डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड दंपति का घर भी तोड़ा गया, जबकि जवान नाइट ड्यूटी पर था। घर में मौजूद उसकी पत्नी के मुताबिक, वे यहां 2006 से रह रहे हैं, और गांव में उनके पास कोई घर नहीं है। कार्रवाई के दौरान कई महिलाओं की रोती हुई तस्वीरें भी सामने आई हैं। महिलाएं सवाल कर रही थीं- हम कहां जाएंगे। पीड़ित गंगा माड़वी का कहना है कि वे अपने परिवार के साथ पिछले 4 सालों से यहां रह रहे हैं। नक्सली हिंसा के कारण वे अपने गांव को छोड़कर यहां आए थे। प्रशासन से बातचीत के बाद उन्होंने घर बनाया और नियमित रूप से टैक्स भी जमा कर रहे थे। अब प्रशासन घरों को तोड़ रहा है। गांव वापस गए तो नक्सली मार देंगे।

Web site : www.krantisamay.com & epaper.krantisamay.com www.facebook.com/krantisamay1 www.twitter.com/krantisamay1

ईरान की उथल-पुथल एवं अमेरिका से टकराव गंभीर चुनौती

(लेखक - ललित गर्ग)

ईरान में बार-बार उभरती उथल-पुथल केवल किसी एक घटना, किसी एक फैसले या किसी एक पीढ़ी का आक्रोश नहीं है, बल्कि यह उस ऐतिहासिक, वैचारिक और भू-राजनीतिक संरचना की परिणति है, जिसने 1979 की इस्लामिक क्रांति के बाद से इस देश को आकार दिया है। आज जब सड़कों पर विरोध के दृश्य, सोशल मीडिया पर आक्रोश और पश्चिमी विश्लेषकों की ओर से सत्ता परिवर्तन की अटकलें तेज हैं, तब यह समझना जरूरी हो जाता है कि ईरान का संकट साधारण आंतरिक असंतोष नहीं, बल्कि वैश्विक शक्ति-संतुलन से गहराई से जुड़ा हुआ प्रश्न है। ईरान की आंतरिक उथल-पुथल एवं अस्थिरता के साथ-साथ उसका अमेरिका के साथ टकराव युद्ध की स्थितियों एवं वैश्विक असंतुलन का बड़ा कारण बन रहा है।

ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ता टकराव केवल द्विपक्षीय तनाव नहीं है, बल्कि इसके दुष्प्रभाव पूरी दुनिया पर पड़ सकते हैं। इस संघर्ष से पश्चिम एशिया में युद्ध का खतरा बढ़ता है, जिसका सीधा असर वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति और तेल की कीमतों पर पड़ सकता है। होर्मुज जलडमरूमध्य में किसी भी तरह की अस्थिरता अंतरराष्ट्रीय व्यापार की धमनियों को बाधित कर सकती है, जिससे महंगाई और आर्थिक मंदी का खतरा बढ़ेगा। इसके साथ ही यह टकराव क्षेत्रीय देशों को प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से युद्ध में खींच सकता है, जिससे शरणार्थी संकट, आतंकवाद और साम्प्रदायिक तनाव गहराने की आशंका है। महाशक्तियों के परस्पर टकराव की स्थिति में विश्व राजनीति और अधिक धूवीकृत होगी, अंतरराष्ट्रीय सहयोग कमजोर पड़ेगा और शांति की जगह अविश्वास व सैन्य प्रतिस्पर्धा का वातावरण बनेगा, जिसका खामियाजा अंततः पूरी मानवता को भुगतना पड़ सकता है।

1979 की इस्लामिक क्रांति ने ईरान में केवल शाह मोहम्मद रज़ा पहलवी को सत्ता से हटाकर एक नई सरकार स्थापित नहीं की थी, बल्कि एक ऐसी वैचारिक-राजनीतिक संरचना रची थी, जिसमें धर्म, राजनीति और सुरक्षा-तंत्र एक-दूसरे में घुलमिल गए। 'विलायत-ए-फकीह' की अवधारणा के तहत सर्वोच्च धार्मिक नेतृत्व को अंतिम राजनीतिक अधिकार सौंपा गया। इसी व्यवस्था के संरक्षण और विस्तार के लिए इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर यानी आईआरजीसी को खड़ा किया गया, जो समय के साथ केवल सैन्य शक्ति नहीं, बल्कि आर्थिक, राजनीतिक और वैचारिक ताकत का भी केंद्र बन गया। यही कारण है कि ईरान की व्यवस्था को केवल सरकार या शासन कहकर नहीं समझा जा सकता; यह एक संपूर्ण तंत्र है, जिसे हटाने के लिए केवल विरोध-प्रदर्शन पर्याप्त नहीं होते।

ईरान ने पिछले चार दशकों में कई बड़े जनांदोलन देखे हैं। 2009 का ग्रीन मूवमेंट, 2017-18 की आर्थिक असंतोष की लहर, 2019 में ईंधन मूल्य वृद्धि के खिलाफ उग्र प्रदर्शन और 2022 में सामाजिक स्वतंत्रताओं को लेकर उठी आवाजेंकृहर बार यह माना गया कि शायद अब व्यवस्था डगमगाएगी। लेकिन हर बार वही सत्ता, वही ढांचा और वही शक्ति-संतुलन कायम रहा। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि ईरान में सुरक्षा-तंत्र राज्य से अलग नहीं, बल्कि राज्य का ही विस्तार है। अरब स्प्रिंग के दौरान मिस्र या तुर्किए में सेनाओं ने अंततः राष्ट्र-राज्य को बचाने का रास्ता चुना, लेकिन ईरान में आईआरजीसी खुद को क्रांति और इस्लामिक रिपब्लिक का संरक्षक मानती है, न कि केवल सीमाओं की रक्षा करने वाली संस्था। फिर भी यह कहना गलत होगा कि ईरान की व्यवस्था पर कोई दबाव नहीं है। वास्तव में, आज का दबाव पहले से कहीं अधिक जटिल और गहरा है। इसका सबसे बड़ा कारण है पीढ़ीगत बदलाव। ईरान की आबादी का बड़ा हिस्सा युवा है, जिसने 1979 की क्रांति न देखी है और न ही उससे भावनात्मक रूप से जुड़ा है। उनके लिए क्रांति कोई जीवित स्मृति नहीं, बल्कि इतिहास की किताबों का अध्याय है। उनकी आकांक्षाएं इंटरनेट, वैश्विक संस्कृति, शिक्षा, रोजगार और व्यक्तिगत स्वतंत्रताओं से प्रेरित हैं। जब ये आकांक्षाएं एक सख्त सामाजिक-राजनीतिक व्यवस्था से टकराती हैं, तो असंतोष स्वाभाविक रूप से जन्म लेता है।

इस असंतोष को और तीखा बनाया है दशकों से चले आ रहे अमेरिकी और पश्चिमी प्रतिबंधों ने। इन प्रतिबंधों ने ईरान की अर्थव्यवस्था को गंभीर रूप से प्रभावित किया है। तेल निर्यात सीमित हुआ, विदेशी निवेश रुका, मुद्रा कमजोर पड़ी और महंगाई ने आम नागरिक की कमर तोड़ दी। विकास और आधुनिकीकरण की गति धीमी पड़ी, जिससे खासकर शहरी मध्यम वर्ग और युवा वर्ग में भविष्य को लेकर निराशा बढ़ी। आज ईरान के कई नागरिक यह सवाल पूछ रहे हैं कि क्या अमेरिका और इजराइल के साथ अंतहीन दुश्मनी का बोझ उन्हीं के कंधों पर डाला जाना जरूरी है। धीरे-धीरे यह वैचारिक टकराव राष्ट्रवादी गौरव से अधिक सामाजिक बोझ के रूप में देखा जाने लगा है। अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ता तनाव इस पूरे परिदृश्य को और खतरनाक बना देता है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से ईरान से व्यापार करने वाले देशों पर अतिरिक्त टैरिफ लगाने के आदेश और सैन्य हस्तक्षेप के संकेतों ने पश्चिम एशिया को एक बार फिर युद्ध के मुहाने पर ला खड़ा किया है। ईरान आज 1979 के बाद से शायद सबसे गंभीर बाहरी दबाव का सामना कर रहा है। यह टकराव केवल दो देशों के बीच का संघर्ष नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा भू-राजनीतिक खेल बन चुका है, जिसमें महाशक्तियां अपने-अपने हित साधना चाहती हैं।

अकसर यह धारणा बनाई जाती है कि बाहरी हस्तक्षेप से ईरान में सत्ता परिवर्तन संभव है। लेकिन इतिहास बताता है कि ईरान में विदेशी दखलअंदाजी ने हमेशा उल्टा असर डाला है। 1953 में मोसादेग सरकार के तख्तापलट से लेकर आज तक, 'विदेशी साजिश' का कथानक ईरानी राष्ट्रवाद को मजबूत करता रहा है।

बाहरी समर्थन से होने वाले आंदोलनों को जनता का व्यापक और स्थायी समर्थन नहीं मिल पाता। यही वजह है कि विपक्षी नेतृत्व, जो अक्सर देश से बाहर बैठा होता है, ईरान के भीतर विश्वसनीय विकल्प नहीं बन सका। इसके अलावा, ईरान वेनेजुएला नहीं है। यह एक बड़ा, संगठित और रणनीतिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण देश है, जिसकी पकड़ इराक, सीरिया, लेबनान और यमन तक फैली हुई है। यहां किसी भी प्रकार का सैन्य हस्तक्षेप पूरे पश्चिम एशिया को आग में झोंक सकता है। इजराइल, खाड़ी देश, अमेरिका और यूरोपीय शक्तियां-सब इसके प्रभाव में आएंगे। चीन और रूस भी एक अस्थिर ईरान नहीं चाहते, क्योंकि वह उनके क्षेत्रीय और वैश्विक हितों के खिलाफ होगा। यह बहुधूवीय संतुलन ईरान की व्यवस्था को एक अप्रत्यक्ष सुरक्षा कवच प्रदान करता है।

ईरान के भीतर आम नागरिकों का गुस्सा अब केवल आर्थिक कुप्रबंधन या भ्रष्टाचार तक सीमित नहीं रह गया है। एक बड़ा वर्ग यह मानने लगा है कि शासन की प्राथमिकताएं आम लोगों की जरूरतों से कट चुकी हैं। जब नागरिक भोजन, रोजगार और सम्मानजनक जीवन की मांग कर रहे हों, तब बाहरी दुश्मनों के खिलाफ वैचारिक युद्ध और यहूदी-विरोधी राजनीति उन्हें खोखली प्रतीत होती है। कई ईरानी मानते हैं कि इसी नीति ने देश को अंतरराष्ट्रीय अलगाव में धकेला और आर्थिक बर्बादी को जन्म दिया। यदि ईरान में बाहरी मदद से सत्ता परिवर्तन की कोशिश होती है, तो इसके परिणाम केवल ईरान तक सीमित नहीं रहेंगे। मध्य पूर्व में शक्ति-संतुलन बुरी तरह बिगड़ सकता है। शिया-सुन्नी तनाव, इजराइल-ईरान संघर्ष और वैश्विक ऊर्जा बाजार-सब पर इसका गहरा असर पड़ेगा। भारत के लिए यह स्थिति विशेष रूप से चुनौतीपूर्ण होगी। भारत के ईरान के साथ ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और रणनीतिक संबंध रहे हैं। चाबहार बंदरगाह से लेकर ऊर्जा सुरक्षा तक, ईरान भारत की विदेश नीति में अहम स्थान रखता है। ऐसे में भारत को अत्यंत सावधानी के साथ अपने रणनीतिक संतुलन को बनाए रखना होगा, ताकि वह किसी एक ध्रुव का मोहरा बनने के बजाय अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा कर सके। अंततः, ईरान की वर्तमान उथल-पुथल यह संकेत देती है कि व्यवस्था पर दबाव वास्तविक है, लेकिन तात्कालिक पतन की भविष्यवाणियां अक्सर जल्दबाजी साबित होती हैं। यह संघर्ष केवल सत्ता परिवर्तन का नहीं, बल्कि पहचान, वैचारिक दिशा और भविष्य की कल्पना का संघर्ष है। ईरान का भविष्य संभवतः न तो अचानक क्रांति से बदलेगा और न ही केवल दमन से स्थिर रहेगा। यह एक लंबी, जटिल और अंतर्द्वंद्वों से भरी प्रक्रिया होगी, जिसके परिणाम न केवल ईरान, बल्कि पूरी दुनिया की राजनीति को प्रभावित करेंगे।

(लेखक, पत्रकार, स्तंभकार)

(यह लेखक के व्यक्तिगत विचार हैं इससे संपादक का सहमत होना अनिवार्य नहीं है)

बाहरी समर्थन से होने वाले आंदोलनों को जनता का व्यापक और स्थायी समर्थन नहीं मिल पाता। यही वजह है कि विपक्षी नेतृत्व, जो अक्सर देश से बाहर बैठा होता है, ईरान के भीतर विश्वसनीय विकल्प नहीं बन सका। इसके अलावा, ईरान वेनेजुएला नहीं है। यह एक बड़ा, संगठित और रणनीतिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण देश है, जिसकी पकड़ इराक, सीरिया, लेबनान और यमन तक फैली हुई है।

संपादकीय

कॉलेज का कलेजा

दिल्ली विश्वविद्यालय के दयाल सिंह इवनिंग कॉलेज का नाम बदलने की कोशिशें उन्नीसवीं सदी के एक दूरदर्शी और परोपकारी सरदार दयाल सिंह मजीठिया जी की स्मृति और विरासत की घोर अवहेलना को ही दर्शाती हैं। यह कॉलेज उन्हीं के नाम पर दिल्ली में स्थापित और प्रतिष्ठित है। 'द ट्रिब्यून' और 'पंजाब नेशनल बैंक' के संस्थापक रहे सरदार दयाल सिंह मजीठिया ने एक ऐसे धर्मनिरपेक्ष व समावेशी कॉलेज की स्थापना का स्वप्न साकार करना चाहा, जहां जनहित में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दी जा सके। उल्लेखनीय है कि दिल्ली स्थित इस संस्थान का समृद्ध इतिहास 1910 से तब शुरू होता है, जब मजीठिया जी के निधन के बारह वर्ष बाद लाहौर में इसकी स्थापना हुई थी। लेकिन आज कॉलेज प्रबंधन की ओर से दलील दी जा रही है कि एक ही नाम से डे कॉलेज और इवनिंग कॉलेज संचालित नहीं किए जा सकते हैं। यह कहना तार्किक नहीं लगता कि नाम बदलने से प्रशासनिक कार्यों में किसी भी तरह की सुविधाजनक स्थिति भी बन सकती है। वहीं दूसरी ओर, यह कॉलेज के कलेजे रूपी गरिमामय विरासत और जनभावनाओं को नजरअंदाज करने जैसा है। यहां यह तथ्य भी उल्लेखनीय है कि इस बदलाव की कोशिशों के कानून पहलू भी ऐसा करने की इजाजत नहीं देते। दरअसल, वर्ष 1978 में हस्तांतरण डीड की धारा 12, जिसके तहत ही दिल्ली विश्वविद्यालय यानी डीयू ने कॉलेज का अधिग्रहण किया था, में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि 'संस्थान दयाल सिंह कालेज के नाम से ही जाना जाता रहेगा।' इस धारा का उल्लंघन करने की स्थिति में भूमि अधिकार छीनने और जबरन विस्थापन जैसी गंभीर कार्रवाई भी की जा सकती है। निश्चित रूप से इस तरह का जोखिम कोई भी जिम्मेदार प्रशासन हल्के में नहीं लेना चाहेगा। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि संकाय सदस्यों को सिख योद्धा बंदा सिंह बहादुर के नाम पर कॉलेज का नाम बदलने के प्रस्ताव की जानकारी तब मिली जब पिछले दिनों दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति ने वीर बाल दिवस के मौके पर इसकी सार्वजनिक रूप से घोषणा की थी। यहां उल्लेखनीय है कि दयाल सिंह इवनिंग कॉलेज एक कालखंड की गरिमामय स्मृतियों को सहेजे हुए है। भारत मां के महान सपूत सरदार दयाल सिंह मजीठिया ने अपने सारी संपत्ति समाज के लिये समर्पित कर दी थी। उन्होंने अपना जीवन एक स्वतंत्र प्रेस, उत्तर भारत में शिक्षा के प्रसार के लिये एक उच्चस्तरीय कॉलेज तथा जागरूकता के लिये पुस्तकालय की स्थापना के लिये लगाया। जिसका मकसद समाज में प्रगतिशील सोच विकसित करना और अज्ञानता को समाप्त करना ही था। ऐसे में एक पुनीत उद्देश्य के लिये स्थापित कॉलेज का नाम बदलने का प्रबंधनतंत्र द्वारा इस तरह का एकतरफा निर्णय विश्वविद्यालय के मूल सिद्धांत को ही कमजोर करता है। जिसका मूल उद्देश्य परामर्श और आम सहमति से कार्य करना होता है। इन कोशिशों के बीच कॉलेज के शिक्षकों और गैर-शिक्षण कर्मचारियों ने ऐसे किसी प्रयास का विरोध करने का फैसला किया है। कर्मचारी संघ द्वारा पारित प्रस्ताव में कॉलेज की पहचान और भविष्य को प्रभावित करने वाले इस कदम को लेकर असंतोष जताया गया है। छात्रों में भी इस बात को लेकर रोष देखा गया है। इसमें दो राय नहीं कि कोई भी शैक्षणिक संस्थान केवल ज्ञान का केंद्र ही नहीं होता, बल्कि सामूहिक स्मृति का संरक्षक भी होता है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि वर्ष 2017 में भी महाविद्यालय का नाम बदलकर 'वंदे मातरम ् महाविद्यालय ' रखने का प्रयास किया गया था।

ईरान की सड़कों पर उबाल - महंगाई असंतोष और सत्ता संघर्ष के बीच बदलता मध्य एशिया

लेखक - कांतिलाल मांडोत)

पिछले सत्रह से अठारह दिनों से ईरान की सड़कों पर जो दृश्य दिखाई दे रहे हैं, वे केवल किसी एक देश की आंतरिक अशांति की कहानी नहीं हैं बल्कि मध्य एशिया की राजनीति अर्थव्यवस्था और वैश्विक शक्ति संतुलन को झकझोर देने वाली घटना के संकेत भी हैं। राजधानी तेहरान से शुरू हुआ महंगाई विरोधी आंदोलन आज हिंसक विद्रोह का रूप ले चुका है। सरकारी इमारतें जल रही हैं बाजार बंद हैं इंटरनेट और फोन सेवाएं ठप हैं और अस्पतालों के बाहर शवों की कतारें उस मानवीय त्रासदी की गवाही दे रही हैं जिसे दुनिया दूर बैठकर देख रही है। अंतरराष्ट्रीय मीडिया के अनुसार हालात इतने भयावह हैं कि लोग अस्पतालों के बाहर अपने परिजनों की लाशें तलाश रहे हैं। रॉयटर्स के मुताबिक अब तक दो हजार से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है जबकि ईरान इंटरनेशनल जैसी वेबसाइटें यह संख्या बारह हजार तक बता रही हैं। मौतों के आंकड़ों में भारी अंतर इस बात का प्रमाण है कि ईरान में सूचना पर कितना कड़ा नियंत्रण है और सच्चाई तक पहुंचना कितना कठिन हो गया है।

ईरान में विरोध प्रदर्शन का तात्कालिक कारण महंगाई और आर्थिक बदहाली है लेकिन इसके पीछे वर्षों से जमा होता असंतोष साफ दिखाई देता है। तेल और प्राकृतिक गैस से समृद्ध यह देश लंबे समय से अमेरिकी प्रतिबंधों के कारण आर्थिक दबाव में है। रियाल की कीमत लगभग शून्य के बराबर पहुंच जाना आम नागरिक की जिंदगी को नरक बना चुका है। रोजमर्रा की जरूरतों की चीजें आम आदमी की पहुंच से बाहर हो चुकी हैं। बेरोजगारी बढ़ रही है युवाओं के सामने भविष्य का कोई स्पष्ट रास्ता नहीं दिख रहा। ऐसे में जब राजधानी तेहरान के ग्रैंड बाजार से व्यापारियों ने हड़ताल शुरू की तो यह चिंगारी कुछ ही दिनों में पूरे देश में फैल गई। देखते ही देखते छात्र आंदोलन से जुड़े विश्वविद्यालयों के परिसर उबलने लगे और फिर यह असंतोष सड़कों पर उतर आया।

ईरान का इतिहास बताता है कि यह देश आंदोलनों और क्रांतियों से अछूता नहीं रहा है। फारस के नाम से पहचाना जाने वाला यह क्षेत्र प्राचीन काल से ही सत्ता और संस्कृति का केंद्र रहा है। साइरस महान से लेकर सिकंदर के आक्रमण और फिर सासानी और पहलवी शासनों तक ईरान ने कई उतार चढ़ाव देखे हैं। 1953 के तख्तापलट और 1979 की इस्लामी क्रांति ने इस देश की राजनीति को पूरी तरह बदल दिया। इस्लामी गणराज्य की स्थापना के बाद सत्ता का केंद्र सुप्रीम लीडर के हाथों में सिमट गया। अयातुल्ला खामेनेई पिछले कई दशकों से ईरान की राजनीति के सबसे ताकतवर चेहरे रहे हैं। लेकिन आज उन्हीं के खिलाफ सड़कों पर नारे लग रहे हैं और उनकी सत्ता को खुली चुनौती दी जा रही है।

सरकार का रुख इस आंदोलन के प्रति बेहद सख्त रहा है। सुप्रीम लीडर ने प्रदर्शनकारियों को दंगाई करार देते हुए कठोर कार्रवाई की चेतावनी दी। सुरक्षाबलों और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़पों में हिंसा लगातार बढ़ती गई। पुलिस थानों पर हमले हुए सुरक्षा अधिकारियों की हत्याएं हुईं और जवाब में सेना तथा रिवोल्यूशनरी गार्ड्स को मैदान में उतार दिया गया। इंटरनेट बंद कर दिया गया ताकि सूचनाओं का प्रवाह रोका जा सके। तेहरान एयरपोर्ट बंद किया गया और राजधानी को लगभग कर्फ्यू जैसी स्थिति में डाल दिया गया। यह सब दर्शाता है कि सत्ता किसी भी कीमत पर नियंत्रण बनाए रखना चाहती है।

इस पूरे घटनाक्रम में अंतरराष्ट्रीय राजनीति की छाया भी साफ नजर आती है। निर्वासित क्राउन प्रिंस रजा पहलवी की सक्रियता और अमेरिकी प्रशासन के साथ उनकी कथित गुप्त मुलाकातों की खबरों ने हालात को और जटिल बना दिया है। रजा पहलवी खुले तौर पर सत्ता परिवर्तन की बात कर रहे हैं और खुद को इस प्रक्रिया का नेतृत्व करने के लिए तैयार बता रहे हैं। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प द्वारा ईरान के साथ कारोबार करने वाले देशों पर अतिरिक्त टैरिफ लगाने की घोषणा ने यह संकेत दिया है कि वाशिंगटन ईरान पर दबाव बढ़ाने के मौके को हाथ से जाने नहीं देना चाहता। हालांकि ईरान हमेशा से अमेरिका और इजराइल का विरोधी रहा है और ऐसे में किसी भी बाहरी हस्तक्षेप को वह अपने खिलाफ साजिश के रूप में पेश करता रहा है।

ईरान में जारी इस संकट का असर केवल वहां की सीमाओं तक सीमित नहीं है। भारत सहित कई देशों के नागरिक और छात्र ईरान में रह रहे हैं जिनकी सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है। कश्मीरी छात्रों के परिवारों की बेचैनी इस बात का उदाहरण है कि यह संकट मानवीय स्तर पर कितनी दूर तक असर डाल रहा है। इसके अलावा ईरान से तेल और व्यापार करने वाले देशों के सामने भी असमंजस की स्थिति है। अगर हालात और बिगड़ते हैं तो वैश्विक ऊर्जा बाजार पर इसका असर पड़ सकता है।

सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या यह आंदोलन किसी बड़े राजनीतिक बदलाव की ओर बढ़ रहा है या फिर सख्त दमन के बाद धीरे धीरे शांत हो जाएगा। ईरान का तंत्र अब तक विरोध को कुचलने में सक्षम रहा है लेकिन इस बार असंतोष की व्यापकता और तीव्रता कुछ अलग संकेत देती है। महंगाई और बेरोजगारी जैसे मुद्दे केवल नारों तक सीमित नहीं हैं बल्कि हर घर की हकीकत बन चुके हैं। जब आर्थिक संकट राजनीतिक असंतोष से जुड़ जाता है तो हालात को संभालना किसी भी सत्ता के लिए मुश्किल हो जाता है।

ईरान आज एक ऐसे चौराहे पर खड़ा है जहां हर रास्ता जोखिम से भरा है। अगर दमन तेज किया गया तो अंतरराष्ट्रीय दबाव और आंतरिक विद्रोह दोनों बढ़ सकते हैं। अगर बातचीत और सुधारों की राह चुनी गई तो सत्ता संरचना में बदलाव की मांग उठ सकती है। मध्य एशिया की राजनीति में ईरान एक महत्वपूर्ण स्तंभ रहा है और वहां की अस्थिरता पूरे क्षेत्र को प्रभावित कर सकती है। ऐसे मंर आने वाले दिन न केवल ईरान के भविष्य को तय करेंगे बल्कि यह भी बताएंगे कि क्या इस्लामी गणराज्य अपने नागरिकों की आवाज सुनने को तैयार है या फिर इतिहास एक बार फिर खुद को दोहराने जा रहा है।

त्रवरिष्ठ पत्रकार, साहित्यकार,स्तम्भकार)

(यह लेखक के व्यक्तिगत विचार हैं इससे संपादक का सहमत होना अनिवार्य नहीं है)

चिंतन मनन

द्वंद्व के बीच शांति की खोज

केवल ज्ञान की बातें करों। किसी व्यक्ति के बारे में दूसरे व्यक्ति से सुनी बातें मत दोहराओ। जब कोई व्यक्ति तुम्हें नकारात्मक बातें कहे, तो उसे वहीं रोक दो, उस पर वास भी मत करो। यदि कोई तुम पर कुछ आरोप लगाये, तो उस पर वास न करो। यह जान लो कि वह बस तुम्हारे बुरे कर्मों को ले रहा है और उसे छोड़ दो। यदि तुम गुरु के निकटतम में से एक हो तो संसार के सारे आरोपों को हंसते हुए ले लोगे। द्वद्व संसार का स्वभाव है और शांति आत्मा का स्वभाव है। द्वद्व के बीच शान्ति की खोज करो। द्वद्व समाप्त करने की चेष्टा द्वद्व को और ज्यादा बढ़ाती है। आत्मा की शरण में आकर विरोध के साथ रहो। जब शान्ति से मन ऊबने लगे तो सांसारिक क्रिया-कलापों का मजा लो। और जब इनसे थक जाओ तो आत्मा की शान्ति में आ जाओ। यदि तुम गुरु के करीब हो, तो दोनों क्रिया कलाप साथ-साथ करोगे। ईश्वर व्यापक हैं। और अनत काल से ईश्वर सभी विरोधों को संभालते आए हैं। यदि ईश्वर सारे विरोधों को ले सकते हैं, तो निश्चित ही तुम भी ऐसा कर सकते हो। जैसे ही तुम विरोध के साथ रहना स्वीकार कर लेते हो, विरोध स्वत- समाप्त हो जाता है। शान्ति चाहने वाले लोग लड़ना नहीं चाहते और इसके विपरीत लड़ाई करने वाले शान्ति पसन्द नहीं करते। शान्ति चाहने वाले लड़ाई से बचना चाहते हैं। आवश्यक यह है कि मन को शांत करें और फिर लड़ें। गीता की यही मूल शिक्षा है। कृष्ण अजरुन को उपदेश देते हैं कि अजरुन युद्ध करो मगर हृदय को शान्त रखकर।

संसार में जैसे ही तुम एक विरोध को समाप्त करते हो तो दूसरा खड़ा हो जाता है। उदाहरण के लिए जैसे ही रूस की समस्या समाप्त हुई, बोस्निया की समस्या खड़ी हो गई। एक समस्या हल होती है, तो दूसरी शुरू हो जाती है। तुम्हें जुकाम हुआ। वह जरा ठीक हुआ नहीं कि फिर कमर में दर्द शुरू हो गया। फिर यह ठीक हो गया। और तो और, शरीर ठीक ठाक है तो मन अशान्त हो जाता है। बिना किसी इरादे के गलतफहमियां पैदा होती हैं, उलझन पैदा होती है। यह तुम्हारे ऊपर नहीं कि तुम उनका समाधान करो। तुम तो बस उन पर ध्यान न दो, बस जीवन्त रहो।

प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना मे सरकारी खजाने से 10000 करोड़ की लूट

(लेखक- सनत जैन)

-कागज़ी ट्रेनिंग, बंद कंपनी को ठेका

प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) को देश के युवाओं को रोजगारोन्मुखी बनाने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी योजना में 10,000 करोड़ की लूट हो गई है? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) की रिपोर्ट में सामने आई जानकारी के अनुसार इस योजना की जमीनी हकीकत पर गंभीर सवाल खड़े हो गये हैं। रिपोर्ट के अनुसार लगभग 33,000 युवाओं की फर्जी ट्रेनिंग दिखाकर करीब 10,000 करोड़ रुपये की लूट सरकारी खजाने से हुई है। केग की रिपोर्ट के अनुसार यह गड़बड़ी केवल प्रशासनिक लापरवाही नहीं, बल्कि एक संगठित घोटाले और लूट की ओर इशारा करती है। कैग की रिपोर्ट का सबसे चौंकाने वाला पहलू यह है, कि एक ही फोटो में सैकड़ों लोगों को ट्रेनिंग लेते हुए दिखाया गया है। प्रशिक्षण केंद्रों ने एक ही तस्वीर अलग-अलग बैचों और अलग-अलग तारीखों मे लाभार्थियों के नाम पर अपलोड कर करोड़ों रुपए का भुगतान लिया है। इसका अर्थ साफ है ट्रेनिंग हुई नहीं, सिर्फ कागज़ों और पोर्टल पर 'कौशल निर्माण' का प्रशिक्षण देकर सुनियोजित साजिश के तहत लूट की गई है। रिपोर्ट में जो गंभीर तथ्य हैं, कैग ने जिन मामलों में लाभार्थियों के बैंक खातों का पता लगाने की कोशिश की, उनके बैंक खाते ही कैग पता नहीं लगा पाई। बैंक अकाउंट के नंबर भी सही नहीं थे। ऐसी स्थिति में लाभार्थियों के खाते में किस तरह से राशि ट्रांसफर हुई है, इसका पता केग नहीं लगा पाई। सरकारी खजाने की राशि एक तरह से किसी एक ऐसे खाते में ट्रांसफर की गई है जिसका उल्लेख केग को कहीं नहीं मिला। जिन युवाओं को प्रशिक्षित दिखाया गया, उनके अस्तित्व, पहचान और भुगतान तीनों पर कैग ने गड़बड़ी का संदेह जताया है। सवाल उठता है, जब आधार, बैंक खाता और डिजिटल ट्रैकिंग जैसी सुविधायें मौजूद थीं. उसके बाद भी फर्जीवाड़ा फलता-फूलता रहा? इससे स्पष्ट है, निगरानी तंत्र या तो अक्षम था, या जानबूझकर आंखें मूंदकर इस लूट में शामिल था। इस कथित घोटाले की जिम्मेदारी प्रशिक्षण प्रदाताओं तक सीमित नहीं की जा सकती है। मंत्रालय, सेक्टर स्किल काउंसिल, थर्ड पार्टी असेसमेंट एजेंसियां और भुगतान प्रणाली इत्यादि सबकी भूमिका की निष्पक्ष और गहन जांच जरूरी है। इस तरह की लूट में तो अपराधिक कार्यवाही की जानी चाहिए थी। कैग जैसी संवैधानिक संस्था बैंक खातों और वास्तविक लाभार्थियों तक नही पहुंच पाई। इसका मतलब है कि सुनयोजित लूट की गई है। यह शासन प्रणाली की पारदर्शिता और प्रक्रिया पर सवाल उठाती है। क्या किसी भी योजना में इतनी बड़े पैमाने पर लूट हो सकती है?

पीएमकेवीवाई जैसे कार्यक्रमों का उद्देश्य युवाओं को हुनर देकर आत्मनिर्भर बनाना था। यदि वही योजना सरकारी खजाने से लूट का साधन बन जाए] बिचौलियों और फर्जी संस्थानों के माध्यम से सरकारी खजाने से लूट की जाए। कैग के इस खुलासे से उन लाखों युवाओं के साथ भी अन्याय हुआ है, जो वास्तव में कौशल प्रशिक्षण की प्रतीक्षा में बैठे हैं। जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है उसके अनुसार 33,000 युवाओं को प्रशिक्षण देने के नाम पर जिस कंपनी को ठेका दिया गया था वह कंपनी रजिस्टर के ठेका की अवधि के 6 साल पहले से बंद थी।

बंद कंपनी को ठेका दिया गया। बिना प्रशिक्षण दिए ही 10,000 करोड रुपए की लूट की गई। इसमें बड़े-बड़े लोगों के शामिल होने की संभावना है। इसका मनी ट्रैल भी जांच एजेंसी पता करना चाहेगी तो उसे पलक झपकते ही इसकी जानकारी मिल जाएगी। इस स्थिति को देखते हुए लूट और घोटाले की जाँच सीबीआई/ईडी जैसी स्वतंत्र एजेंसियों से कराकर, दोषियों पर कठोर कार्यवाही की जाए। केग की इस रिपोर्ट को आधार बनाकर सरकारी योजनाओं की री-डिज़ाइन हो। सरकारी योजनाओं के जमीनी एवं वास्तविक सत्यापन, रियल-टाइम ऑडिट, और लाभार्थी-केंद्रित भुगतान अनिवार्य हो। अन्यथा 'स्किल इंडिया' केवल नारा बनकर रह जाएगा। इसी तरह सरकारी खजाने से योजनाएं तो चलती रहेंगी, इसका वास्तविक लाभ हितग्राहियों को नहीं मिलेगा। 'कागज़ी ट्रेनिंग' का यह सच दिल दहलाने वाला है। जहां पर योजना की शत-प्रतिशत राशि सरकारी खजाने से लूट ली गई।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई बार कह चुके हैं, जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे, तब उस समय केंद्र से 1 रुपये चलता था, बीच रास्ते में पचासी पैसे गायब हो जाते थे।

दुर्भाग्य का विषय है, अब कैग की रिपोर्ट के बाद खजाने से 100 रुपये निकले, वह रास्ते में नहीं मंत्रालय में ही कागजों में लूट लिए गए। यह नया मुहावरा जल्द ही सुनने को मिल सकता है।

Web site : www.krantisamay.com & epaper.krantisamay.com www.facebook.com/krantisamay1 www.twitter.com/krantisamay1

कई शहरों में पेट्रोल-डीजल सस्ता, कुछ जगह बढ़े दाम

ब्रेंट क्रूड 63 डॉलर के नीचे, नोएडा और पटना में राहत, गाजियाबाद में बढ़ोतरी

नईदिल्ली ।

वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में पिछले दो दिनों के दौरान 4 डॉलर से ज्यादा की गिरावट दर्ज की गई है। इसका सीधा असर शुक्रवार सुबह जारी पेट्रोल और डीजल की खुदरा कीमतों पर देखने को मिला। देश के कई शहरों में तेल के दाम घटे हैं, जबकि कुछ जगहों पर मामूली बढ़ोतरी भी दर्ज की गई है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में बीते 24 घंटों के दौरान कच्चे तेल की कीमतों में जोरदार गिरावट आई है। ब्रेंट क्रूड 2.76 डॉलर लुढ़ककर 63.76 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गया है।

वहीं, अमेरिकी डब्ल्यूटीआई क्रूड करीब 1 डॉलर की गिरावट के साथ 59.29 डॉलर प्रति बैरल के स्तर पर कारोबार कर रहा है। कच्चे तेल की इस कमजोरी का असर घरेलू बाजार पर भी दिखने लगा है।

सरकारी तेल कंपनियों के अनुसार उत्तर प्रदेश के गौतमबुद्ध नगर जिले यानी नोएडा में पेट्रोल 16 पैसे सस्ता होकर 94.74 रुपये प्रति लीटर बिक रहा है। डीजल की कीमत में भी 20 पैसे की गिरावट आई है और यह 87.81 रुपये प्रति लीटर हो गया है।

वहीं गाजियाबाद में पेट्रोल 12 पैसे महंगा होकर 94.70 रुपये प्रति लीटर और डीजल 14 पैसे बढ़कर 87.81 रुपये प्रति लीटर पहुंच गया है। बिहार की राजधानी पटना में भी आज उपभोक्ताओं को राहत मिली है।

यहां पेट्रोल 18 पैसे गिरकर 105.23 रुपये प्रति लीटर हो गया है, जबकि डीजल 17 पैसे सस्ता होकर 91.49 रुपये प्रति लीटर बिक रहा है।

देश के चार प्रमुख महानगरों में आज पेट्रोल-डीजल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ। दिल्ली में पेट्रोल 94.72 रुपये और डीजल 87.62 रुपये प्रति लीटर है। मुंबई में पेट्रोल 103.44 रुपये और डीजल 89.97 रुपये, चेन्नई में पेट्रोल 100.76 रुपये और डीजल 92.35 रुपये तथा कोलकाता में पेट्रोल 104.95 रुपये और डीजल 91.76 रुपये प्रति लीटर के भाव पर मिल रहा है।

रुपया गिरावट पर बंद

मुंबई ।

अमेरिकी डॉलर के मुकाबले शुक्रवार को भारतीय रुपया 42 पैसे टूटकर 99.76 पर बंद हुआ। आज सुबह रुपये में लगातार तीसरे सत्र में गिरावट रही और यह 10 पैसे टूटकर 90.44 प्रति डॉलर पर पहुंच गया। विदेशी पूंजी की निरंतर निकासी और डॉलर के मजबूत रुख से घरेलू मुद्रा पर दबाव बना रहा। विदेशी मुद्रा कारोबारियों ने बताया कि कच्चे तेल की कम कीमतों और शेयर बाजार के सकारात्मक माहौल ने घरेलू मुद्रा को हालांकि निचले स्तर पर समर्थन दिया। अंतरबैंक विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में रुपया 90.37 प्रति डॉलर पर खुला। फिर डॉलर के मुकाबले 90.44 पर आ गया जो पिछले बंद भाव से 10 पैसे की गिरावट दिखाता है। रुपया बुधवार को अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 90.34 पर बंद हुआ था। मुंबई में बृहन्मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) चुनाव के अवकाश के मद्देनजर गुरुवार को विदेशी मुद्रा बाजार बंद थे। इस बीच छह प्रमुख मुद्राओं के मुकाबले अमेरिकी डॉलर की स्थिति को दिखाने वाला डॉलर सूचकांक 0.02 फीसदी की गिरावट के साथ 99.10 पर रहा।

एलटीआई माइंडट्री को 3,000 करोड़ का मिला ठेका

नई दिल्ली ।

एलटीआई माइंडट्री को केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) से इंसाइट 2.0 परियोजना का ठेका मिला है। इस परियोजना के तहत भारत के राष्ट्रीय कर विश्लेषण मंच का आधुनिकीकरण किया जाएगा और इसे एआई-संचालित प्रणाली में परिवर्तित किया जाएगा। परियोजना का कुल मूल्य लगभग 3,000 करोड़ रुपये है और इसे सात वर्षों में पूरा किया जाएगा। यह मंच नीति-निर्माताओं को वास्तविक समय की जानकारी प्रदान करेगा, जिससे कर प्रशासन और नीति निर्माण में तेजी और पारदर्शिता आएगी। एलटीआई माइंडट्री के डिजिटल बदलाव और एआई समाधान में नेतृत्व को भी यह परियोजना मजबूत बनाएगी। इंसाइट 2.0 से भारत का कर प्रशासन स्मार्ट, डेटा-सक्षम और भविष्य की चुनौतियों के अनुकूल बनेगा।

शेयर बाजार तेजी के साथ बंद

सेंसेक्स 188, निफ्टी 29 अंक उछला

मुम्बई ।

भारतीय शेयर बाजार शुक्रवार को तेजी के साथ बंद हुआ। सप्ताह के अंतिम कारोबारी दिन बाजार में ये तेजी दुनिया भर से मिले अच्छे संकेतों के साथ ही आईटी शेयरों में खरीदारी हावी होने से आई है। दिन भर के कारोबार के बाद 30 शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स सेंसेक्स 187.64 अंक बढ़कर 83,570.35 जबकि 50 शेयरों वाला एनएसई निफ्टी 28.75 अंक ऊपर आकर 25,694.35 अंक पर बंद हुआ। आज सेंसेक्स में शामिल 30 कंपनियों में से इन्फोसिस, टेक महिंद्रा, महिंद्रा एंड महिंद्रा, कोटक महिंद्रा बैंक और पावर ग्रिड के शेयरों में सबसे ज्यादा तेजी रही। वहीं इन्फोसिस के शेयर में तो 5 फीसदी से अधिक उछाल आया। इससे आईटी क्षेत्र में भी तेजी रही। कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2026 के लिए कमाई का अनुमान बढ़ाकर निवेशकों को हैरान किया है। इन्फोसिस एआई के क्षेत्र में अपनी मजबूत साझेदारी से बाजार में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने पर जोर दे रहा है। इससे पहले आज घरेलू बाजारों की शुरुआत मजबूती के साथ हुई। खास तौर पर आईटी सेक्टर के दिग्गज शेयरों में जोरदार खरीदारी देखने को मिली, जिससे बाजार को शुरुआती कारोबार में अच्छा सपोर्ट मिला। इन्फोसिस के नेतृत्व में टीसीएस, विप्रो और एचसीएल टेक जैसे अन्य आईटी शेयरों में भी खरीदारी देखने को मिली। अमेरिकी बाजारों में टेक शेयरों की मजबूती और सकारात्मक ग्लोबल संकेतों से आईटी सेक्टर को फायदा मिला। सेंसेक्स मजबूत बढ़त के साथ 83,670 अंक पर खुला और कुछ ही देर में 83,700 अंक के स्तर के ऊपर निकल गया। सुबह शुरुआत के बाद सेंसेक्स 238.09 अंक की तेजी के साथ 83,620.80 अंक पर कारोबार कर रहा था। बैंकिंग और आईटी शेयरों में खरीदारी ने सेंसेक्स को मजबूती प्रदान की। निफ्टी-50 भी तेजी के साथ खुला। निफ्टी ने कारोबार की शुरुआत 25,696 अंक पर की और खुलते ही 25,700 अंक के स्तर को पार कर गया।

गुरुवार को महाराष्ट्र नगर निगम चुनाव के तहत शेयर बाजार बंद रह अमेरिकी शेयर बाजार गुरुवार को बढ़त के साथ बंद हुए। टेक्नोलॉजी और बैंकिंग शेयरों में तेजी से प्रमुख इंडेक्स ऊपर गए। डॉव जोन्स 0.6 फीसदी चढ़ा, जबकि एसएंडपी 500 में 0.26 फीसदी और नैस्डैक में 0.25 फीसदी की बढ़त दर्ज की गई।

एप्पल पर भारत में एंटी-ट्रस्ट मामले में लग सकता है भारी जुर्माना

मुंबई ।

आईफोन बनाने वाली अमेरिकी कंपनी एप्पल को भारत में प्रतिस्पर्धा-विरोधी आचरण के आरोपों के चलते गंभीर मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। भारतीय प्रे तिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) ने एप्पल को अंतिम चेतावनी दी है। आयोग का आरोप है कि कंपनी पिछले एक साल से अधिक समय से आवश्यक जानकारी और जवाब देने में सहयोग नहीं कर रही है। यदि सीसीआई एप्पल के ग्लोबल टर्नओवर के आधार पर जुर्माना तय करता है, तो कंपनी पर करीब 38 अरब डॉलर (लगभग 34.33 लाख करोड़ रुपए) का भारी जुर्माना लग सकता है। यह जुर्माना भारतीय प्रतिस्पर्धा कानून के तहत सबसे बड़े मामलों में से एक माना जा सकता है। एप्पल ने इन आरोपों का खंडन किया है और कहा है कि वह किसी भी तरह का दुरुपयोग नहीं कर रही। मामला फिलहाल दिल्ली हाई कोर्ट में विचाराधीन है। कोर्ट में एप्पल ने पूरी जांच पर रोक लगाने की कोशिश की थी, लेकिन सीसीआई ने इसकी मांग खारिज कर दी। 2024 में जांच एजेंसियों ने रिपोर्ट जारी की थी, जिसमें एप्पल पर आईओएस ऐप बाजार में अपनी मजबूत स्थिति का दुरुपयोग करने और प्रतिस्पर्धा-विरोधी आचरण करने का आरोप लगाया गया था। सीसीआई ने अक्टूबर 2024 में एप्पल से जांच के निष्कर्षों पर आपत्तियां दर्ज करने और वित्तीय जानकारी देने को कहा था, लेकिन कंपनी ने आवश्यक विवरण प्रदान नहीं किया।

बिटकॉइन में भारी गिरावट, 90,261 डॉलर पर

- बिटकॉइन की कीमतों पर वैश्विक आर्थिक और नीतिगत कारक डाल रहे हैं असर

नई दिल्ली ।

पिछले साल 6 अक्टूबर को बिटकॉइन ने 1,26,210.50 डॉलर के सर्वकालिक उच्च स्तर को छुआ, लेकिन इसके बाद कीमत में तेज गिरावट आई। वर्तमान में यह लगभग 90,261 डॉलर पर कारोबार कर रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस गिरावट के दौरान घबराना सही नहीं है, बल्कि दीर्घकालिक निवेशक इसे अवसर के रूप में देख सकते हैं। बाजार के जानकारों ने कहा कि बाजार की अस्थिरता के बावजूद निवेशकों को अनुशासित तरीके से बिटकॉइन की अतिरिक्त यूनिट जमा करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि गिरावट का लाभ उठाकर दीर्घकालिक दृष्टिकोण बनाए रखना फायदेमंद साबित हो सकता है। बिटकॉइन की कीमतों पर वैश्विक आर्थिक और नीतिगत कारक असर डाल रहे हैं। बैंक ऑफ जापान द्वारा ब्याज दरों में बढ़ोतरी और अमेरिकी फेड द्वारा भविष्य की दरों में कटौती को लेकर सतर्क संकेतों ने बाजार में अनिश्चितता बढ़ाई। अमेरिका में लंबे समय तक कामकाज बंद रहने से निवेशकों में सतर्कता और बढ़ गई। अक्टूबर में रैली के बाद चौथी तिमाही में संस्थागत निवेशकों ने मुनाफावसूली की। बाजार के विशेषज्ञों ने कहा कि अत्यधिक लीवरेज वाली पोज़ीशन को समाप्त किया गया। विशेषज्ञों का सुझाव है कि निवेशक फटाफट निर्णय न लें। बाजार की अस्थिरता के बावजूद दीर्घकालिक दृष्टिकोण अपनाना और अनुशासित निवेश करना लाभकारी हो सकता है।

स्मार्टफोन और इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादों की कीमतें बढ़ेंगी

- महंगाई का मुख्य कारण है मेमोरी चिप्स की बढ़ती कीमतें और सप्लाई की कमी

नई दिल्ली ।

2026 के बजट से पहले उपभोक्ताओं को इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स की कीमतें घटने की उम्मीद थी, लेकिन इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स इसके उलट संकेत दे रहे हैं। एआई और हाई-परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग की बढ़ती मांग के कारण मेमोरी चिप्स महंगी हो रही हैं। एक अध्ययन के अनुसार पिछले कुछ महीनों में चिप्स की कीमतें 40-50 फीसदी तक बढ़ चुकी हैं और आने वाली तिमाहियों में और 20 फीसदी तक बढ़ने की संभावना है। कुछ ब्रांड जैसे विवो और ने थिंग ने जनवरी में अपने स्मार्टफोन के दाम 3,000-5,000 रुपए बढ़ा दिए हैं। वहीं सेससंग जैसी कंपनियां सीधे दाम बढ़ाने के बजाय कैशबैक और डिस्काउंट घटाकर कीमतों को अप्रत्यक्ष रूप से बढ़ा रही हैं। विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि नई लॉन्चिंग में कंपनियां श्रिंकफ्लेशन अपना सकती हैं, यानी डिस्प्ले या अन्य कंपोनेंट्स की क्वालिटी में हल्का कटौती कर सकती हैं। कुछ रिटेलर्स ने नवंबर-दिसंबर में 5-10 फीसदी तक कीमतें बढ़ाई हैं और फरवरी में अतिरिक्त बढ़ोतरी की योजना है। उनके अनुसार स्मार्टफोन की कीमतें अगले कुछ महीनों में कुल मिलाकर 30 फीसदी तक बढ़ सकती हैं। इससे 20,000 रुपए से कम कीमत वाले स्मार्टफोन्स पर सबसे ज्यादा असर पड़ेगा और बाजार में 10-12 फीसदी तक गिरावट आ सकती है। उपभोक्ता फिलहाल खरीदारी को रोककर सही समय का इंतजार कर रहे हैं।

डाक मार्ग से निर्यात पर भी लागू होंगी निर्यात प्रोत्साहन योजना

- नई पहल से छोटे शहरों और दूरदराज के क्षेत्रों के निर्यातकों को मिलेगा बड़ा लाभ

नई दिल्ली ।

केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) ने शुक्रवार को घोषणा की कि अब आरओडीटीईपी और आरओएससीटीएल एजैसी निर्यात प्रोत्साहन योजनाएं डाक के माध्यम से भेजे जाने वाले माल पर भी लागू होंगी। यह निर्णय 15 जनवरी 2026 से प्रभावी हो गई है। वित्त मंत्रालय ने बताया कि इससे विशेष रूप से छोटे शहरों और दूरदराज के क्षेत्रों के निर्यातकों (एमएसएमई) की प्रतिस्पर्धा में सुधार होगा और डाक निर्यात को बढ़ावा मिलेगा। ड्यूटी ड्रॉबैक योजना के तहत निर्यातक को उस माल के निर्माण में इस्तेमाल किए गए कच्चे माल पर चुकाए गए सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क का पूरा या आंशिक रिफंड मिलेगा। इसके अलावा आरओडीटीईपी और आरओएससीटीएल योजनाओं के माध्यम से राज्य एवं केंद्रीय करों में छूट दी जाएगी। कर विशेषज्ञों बताया कि डाक मार्ग के लिए इन लाभों का विस्तार करने से दूरस्थ क्षेत्रों के एमएसएमई के लिए लंबी अवधि से चली आ रही अनुपालन बाधाओं को दूर किया गया है। सीबीआईसी ने इसके लिए डाक निर्यात (इलेक्ट्रॉनिक घोषणा और प्रसंस्करण) विनियम, 2022 में संशोधन किया। इसके तहत निर्यातक अब डाक मार्ग से किए गए निर्यात पर सभी लाभों का दावा कर सकेंगे। भारत में वर्तमान में 28 विदेशी डाकघर अधिसूचित हैं। इसके अलावा, डाक आयात विनियम, 2025 और आईजीएसटी रिफंड के स्वचालन जैसे कदमों से डाक माध्यमों के जरिए अंतरराष्ट्रीय व्यापार को और सुगम बनाया गया है।

मिडकैप सूचकांक का कमजोर प्रदर्शन, लार्जकैप ने बढ़त बनाई

नई दिल्ली ।

कैलेंडर वर्ष 2025 में तेजी से बढ़ते मिडकैप शेयरों ने पिछले दो साल के रुझान को पलटते हुए कमजोर प्रदर्शन किया। बीएसई मिडकैप सूचकांक वर्ष 2025 में केवल 1.1 प्रतिशत बढ़ा, जबकि 2024 में यह 26.1 प्रतिशत की तेजी दर्ज कर चुका था। यह 2019 के बाद का सबसे खराब सालाना प्रदर्शन है। कुल मिलाकर सूचकांक के 140 में से 84 शेयर (लगभग 61 फीसदी) पिछले साल गिरावट के साथ बंद हुए, जिसमें 17 शेयरों की कीमतें 30 प्रतिशत से अधिक गिरीं। इस बीच बड़े शेयरों ने बेहतर प्रदर्शन किया। बीएसई सेंसेक्स 2025 में 9.1 प्रतिशत बढ़ा, जो 2024 की 8.2 प्रतिशत की बढ़त से थोड़ी बेहतर रही। इससे साफ होता है कि निवेशकों ने जोखिम कम करने के लिए मिडकैप की तुलना में लार्जकैप शेयरों को प्राथमिकता दी। मिडकैप में अलग-अलग शेयरों के प्रदर्शन में बड़ा अंतर रहा। एलएंडटी फाइनेंस ने सबसे अच्छा प्रदर्शन किया, जो 133 प्रतिशत चढ़ा। दूसरी ओर, ओला इलेक्ट्रिक का बाजार पूंजीकरण लगभग 58 प्रतिशत घटा। कुल मिलाकर, मिडकैप सूचकांक में 18 शेयरों ने 30 प्रतिशत या उससे अधिक की तेजी दिखाई, जिनमें से 12 शेयरों में 50 प्रतिशत या उससे ज्यादा बढ़त रही।

अनधिकृत वॉकी-टॉकी बेचने वाले ई-कॉमर्स प्लेटफ़ॉर्म्स पर 44 लाख का जुर्माना

- लाइसेंस छूट वाले आवृत्ति बैंड के बाहर वाले पीएमआर उपकरणों की बिक्री करने का मामला

नई दिल्ली ।

केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (सीसीपीए) ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 और दूरसंचार कानूनों का उल्लंघन करने वाले ई-कॉमर्स प्लेटफ़ॉर्म्स के खिलाफ स्वतः संज्ञान लेते हुए कार्रवाई शुरू की। यह कार्रवाई उन प्लेटफ़ॉर्म्स के खिलाफ की गई, जिन्होंने अनधिकृत वॉकी-टॉकी (पीएमआर) को सूचीबद्ध और बेचा। सीसीपीए ने विभिन्न प्लेटफ़ॉर्म्स पर 16,970 से अधिक गैर-अनुपालन उत्पादों की पहचान की। जिनमें मीशो, मेटा प्लेटफ़ॉर्म्स (फेसबुक मार्केटप्लेस), फ्लिपकार्ट, अमेजन, चिमिया, जियोमार्ट, टॉक प्रो, मास्कमैन टॉयज, ट्रेडइंडिया, अंतरिक्ष टेक्नोलॉजीज, वरदानमार्ट, इंडियामार्ट और कृष्णा मार्ट शो मिल हैं। प्राधिकरण ने पाया कि ये मंच लाइसेंस छूट वाले आवृत्ति बैंड (446.0-446.2 एमएचजेड) के बाहर वाले पीएमआर उपकरणों की बिक्री कर रहे थे। इन उपकरणों के लिए उपकरण प्रकार अनुमोदन (ईटीए) प्रमाणन और लाइसेंसिंग आवश्यकताओं का पालन नहीं किया गया। उपभोक्ता मामलों की सचिव निधि खरे ने बताया कि प्राधिकरण ने उपभोक्ता अधिकारों के उल्लंघन, भ्रामक विज्ञापनों एवं अनुचित व्यापार प्रथाओं के लिए मीशो, मेटा प्लेटफ़ॉर्म्स इंक (फेसबुक मार्केटप्लेस), फ्लिपकार्ट तथा अमेजन पर 10 लाख रुपये और चिमिया, जियोमार्ट, टॉक प्रो और मास्कमैन टॉयज पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। उन्होंने बताया कि मीशो, मेटा, चिमिया, जियोमार्ट और टॉक प्रो ने अपना जुर्माना अदा कर दिया है। शेष मंचों ने अभी भुगतान नहीं किया है।मौजूदा नियमों के तहत, लाइसेंस छूट केवल 446.0-446.2 मेगाहर्ट्ज बैंड में ही संचालित होने वाले पीएमआर पर लागू होती है। लघु-श्रेणी रेडियो आवृत्ति उपकरणों के उपयोग संबंधी नियम 2018 का नियम पांच यह अनिवार्य करता है कि विनिर्माताओं तथा विक्रेताओं को ऐसे उपकरणों के आयात, बिक्री या संचालन से पहले ईटीए (अनुमति और प्रमाणीकरण) प्राप्त करना होगा।

भारत-ईयू एफटीए पर 27 जनवरी को बड़ा ऐलान संभव

- दिल्ली शिखर सम्मेलन में तय होगी समझौते की रूपरेखा

नई दिल्ली ।

भारत और यूरोपीय संघ (ईयू) के बीच मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) पर बातचीत के निष्कर्ष की घोषणा 27 जनवरी को हो सकती है। यह घोषणा ईयू के शीर्ष नेतृत्व की भारत यात्रा (25-27 जनवरी) के दौरान, 16वें भारत-ईयू शिखर सम्मेलन में होने की संभावना है। हालांकि अंतिम समझौते पर तत्काल हस्ताक्षर की संभावना कम है, लेकिन समझौते की रूपरेखा तय होने की उम्मीद है। यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो लुइस सैंटोस दा कोस्टा और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ सह-अध्यक्षता करेंगे। दोनों नेता इस वर्ष के गणतंत्र दिवस परेड के मुख्य अतिथि भी होंगे। पिछले तीन महीनों में वार्ता के ÷अंतिम और सबसे कठिन÷ चरण में रही। कुल 24 मुद्दों में से 20 पर सहमति बन चुकी है, जबकि कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पर अभी भी चर्चा चल रही है। वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल के अनुसार, नेता बैठक से पहले प्रयास जारी हैं। अंतिम पैकेज में कृषि शामिल नहीं होगी। यूरोपीय आयोग ने स्पष्ट किया कि कृषि को समझौते से बाहर रखा गया है। ब्रसेल्स ने यूरोपीय वाइन और शराब पर 150त्न शुल्क कम करने पर भारत के साथ सहमति बनाई है। कठिन बिंदुओं में इस्पात आयात पर ईयू नीतियां और भारत के लिए कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म शामिल हैं। ईयू के लिए वाहन वाइन और कृषि उत्पादों पर कम शुल्क प्रमुख हित हैं। इसके लिए वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल और वाणिज्य सचिव अग्रवाल ने जनवरी में ब्रसेल्स में उच्चस्तरीय वार्ता की।

भारत में बेरोजगारी दर 4.8 फीसदी पर, श्रम बाजार सक्रिय

नई दिल्ली ।दिसंबर में बेरोजगारी राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) के अनुसार दिसंबर 2025 में भारत की बेरोजगारी दर बढ़कर 4.8 फीसदी हो गई, जो नवंबर के 4.7 फीसदी से थोड़ी अधिक है। यह आठ महीने में दूसरा निचला स्तर है। शहरी क्षेत्र में बेरोजगारी दर 6.7 फीसदी तक बढ़ी, जबकि ग्रामीण क्षेत्र में यह स्थिर 3.9 फीसदी बनी रही। महिलाओं की बेरोजगारी 4.7 फीसदी और पुरुषों की 4.9 फीसदी रही, जो पिछली रिपोर्ट से मामूली बढ़ोतरी दर्शाती है। श्रमबल हिस्सेदारी दर बढ़कर 56.1 फीसदी हो गई। ग्रामीण श्रमबल हिस्सेदारी 59 फीसदी और शहरी 50.2 फीसदी रही। 15 साल या उससे अधिक उम्र की महिलाओं की श्रमबल हिस्सेदारी 35.5 फीसदी तक पहुंच गई।

चांदी की कीमतों में बड़ी गिरावट, सोना भी हुआ सस्ता

- चांदी का भाव 2,89,050 प्रति किलो, सोना 1,42,799 रुपए प्रति 10 ग्राम

नई दिल्ली ।

घरेलू वायदा बाजार में शुक्रवार को सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (एमसीएक्स) पर बाजार खुलते ही चांदी की कीमतों में तेज दबाव देखने को मिला और यह करीब 6,000 रुपये प्रति किलो तक टूट गई। वहीं सोने की कीमतों में भी मामूली कमजोरी नजर आई, जिससे निवेशकों में थोड़ी सतर्कता देखी गई। 5 मार्च डिलीवरी वाली चांदी पिछले कारोबारी सत्र में 2,91,577 रुपये प्रति किलो पर बंद हुई थी। शुक्रवार को यह गिरावट के साथ 2,87,127 रुपये प्रति किलो पर खुली। शुरुआती कारोबार में चांदी 2,85,513 रुपये के निचले स्तर तक फिसल गई, जबकि इसका ऊपरी स्तर 2,88,901 रुपये रहा। इस समय चांदी 2,527 रुपये की गिरावट के साथ 2,89,050 रुपये प्रति किलो पर कारोबार कर रही थी। बाजार में आई इस गिरावट को मुनाफावसूली और वैश्विक संकेतों से जोड़कर देखा जा रहा है। वहीं सोने की कीमतों में भी हल्की गिरावट देखने को मिली। 5 फरवरी डिलीवरी वाला सोना पिछले सत्र में 1,43,121 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था, जबकि शुक्रवार को यह 1,42,589 रुपये पर खुला। शुरुआती कारोबार में सोना 1,42,400 रुपये के निचले स्तर तक गया और 1,42,837 रुपये के उच्च स्तर तक पहुंचा। इस समय सोना 322 रुपये की गिरावट के साथ 1,42,799 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता नजर आया। हालांकि कीमतों में गिरावट दर्ज की गई है, लेकिन लंबी अवधि के लिहाज से कीमती धातुओं का रुझान मजबूत बना हुआ है। साल 2026 में अब तक सोने की कीमत करीब 5 फीसदी और चांदी की कीमत लगभग 15 फीसदी बढ़ चुकी है। वहीं बीते एक साल में सोने ने करीब 80 फीसदी का रिटर्न दिया है, जबकि चांदी ने लगभग 192 फीसदी की जबरदस्त तेजी दिखाई है।

Web site : www.krantisamay.com & epaper.krantisamay.com www.facebook.com/krantisamay1 www.twitter.com/krantisamay1

रोहित शर्मा का अपमान ! गौतम गंभीर-अजीत अगरकर ने की नाइंसाफी ? पूर्व क्रिकेटर ने खोला मोर्चा

नई दिल्ली (एजेंसी)। पूर्व भारतीय बल्लेबाज मनोज तिवारी ने रोहित शर्मा को भारत की वनडे कप्तानी से हटाए जाने की कड़ी आलोचना की है और संकेत दिया है कि इस फैसले में मुख्य कोच गौतम गंभीर की भूमिका रही है। 37 वर्षीय तिवारी और गंभीर के बीच पहले भी मतभेद रहे हैं और माना जा रहा है कि यह दोनों के बीच बदले की भावना का नतीजा है। उनका मानना है कि रोहित की फॉर्म और अनुभव को देखते हुए अचानक कप्तानी बदलना उनके प्रति अनादर का प्रतीक है।

जून 2024 में टी20 अंतरराष्ट्रीय और पिछले साल मई में टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने के बाद भी रोहित भारत की वनडे टीम के अहम सदस्य बने रहे और उन्हें उम्मीद थी कि 2027 विश्व कप से पहले वे अपने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन पर पहुंच जाएंगे। लेकिन जब भारत ने अक्टूबर में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए अपनी टीम की घोषणा की, तो शुभमन गिल को कप्तान बनाया गया। यह एक चौंकाने वाला और कुछ हद तक विवादास्पद कदम था, जिसने पूरे देश के क्रिकेट प्रशंसकों और विशेषज्ञों के बीच चर्चा का विषय बना दिया। यह और भी उल्लेखनीय था क्योंकि रोहित ने अपने कार्यकाल का शानदार अंत किया था - पिछले महीने आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में जीत कप्तान के रूप में उनका आखिरी मैच था।

तिवारी ने स्पोर्ट्स टुडे को बताया कि मुझे नहीं पता कि इसका मुख्य कारण क्या है। लेकिन अजीत अगरकर को जानते हुए, वह एक प्रभावशाली व्यक्तित्व हैं। वह निर्णय लेने वाले व्यक्ति हैं। ऐसे कदम उठाने में वह पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन क्या उन्हें किसी ने प्रभावित किया था जिसके कारण उन्होंने यह फैसला लिया, यह एक ऐसा मुद्दा है जिस पर हमें गौर करने की जरूरत है। पर्दे के पीछे बहुत कुछ होता है, जिससे मामला पेचीदा हो जाता है। हो सकता है कि यह फैसला मुख्य चयनकर्ता ने लिया हो और उन्होंने इस बारे में खुलकर अपनी राय रखी हो। स्वाभाविक रूप से, कोच की भी इसमें भूमिका रही होगी। कोई भी व्यक्ति अकेले यह फैसला नहीं ले सकता। जो भी फैसला लिया गया है, उसके लिए दोनों बराबर जिम्मेदार हैं।

उन्होंने आगे कहा कि देखिए, मेरी राय में प्लेइंग इलेवन के चयन में बहुत असंगति रही है। अगर मुझे बिल्कुल स्पष्ट कहना हो, तो वनडे मैच देखने में मेरी रुचि कम हो गई है। हाल ही में जो कुछ हुआ है, जैसे टी20 विश्व कप विजेता कप्तान और चैंपियंस ट्रॉफी विजेता कप्तान को कप्तानी से हटाकर नए कप्तान को सौंप देना, जो मुझे लगता है कि जरूरी नहीं था। मैं रोहित के साथ खेल चुका हूं। हमारा एक खास रिश्ता है, इसलिए मुझे यह सब ठीक नहीं लगा। मुझे लगा कि यह उस क्रिकेटर का अपमान है जिसने

दुनिया भर के क्रिकेट प्रेमियों को इतना कुछ दिया है। उसी दिन से मेरी रुचि थोड़ी कम हो गई। बहुत सारे विवाद हैं, और मुझे लगता है कि यह सब स्पष्टता की कमी के कारण हो रहा है।

हैमर थ्रो खिलाड़ी तान्या ने राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया लेकिन नहीं होगा रिकॉर्ड बुक में दर्ज

मंगलुरू (एजेंसी)। अंतरराष्ट्रीय एथलीट तान्या चौधरी ने 85वीं अखिल भारतीय अंतर विश्वविद्यालय चैम्पियनशिप में शुक्रवार को महिला हैमर थ्रो में नया रिकॉर्ड बनाकर स्वर्ण पदक जीता लेकिन उनका यह प्रयास रिकॉर्ड में दर्ज नहीं हो सका क्योंकि इस टूर्नामेंट को राष्ट्रीय महासंघ से मान्यता नहीं मिली है।

तान्या ने खुद स्वीकार किया है कि टूर्नामेंट के लिये उनका डोप टेस्ट भी नहीं हुआ था। भारतीय एथलेटिक्स महासंघ द्वारा राष्ट्रीय रिकॉर्ड की मान्यता के लिए प्रतिस्पर्धा के दौरान डोप टेस्ट जरूरी है। तान्या ने 65.60 मीटर का थ्रो फेंककर सरिता सिंह का 9 साल पुराना 65.25 मीटर का रिकॉर्ड तोड़ा। एएफआई अंतर विश्वविद्यालय चैम्पियनशिप को मान्यता नहीं देता है। तान्या ने 2023 हांगझोउ एशियाई खेलों में भाग लिया था और वह सातवें स्थान पर रही थी।

उन्होंने कहा, 'मुझे 67 मीटर की उम्मीद थी। इस सत्र का लक्ष्य 70 मीटर है और मैं उसकी तैयारी में जुटी हूं। आज डोप टेस्ट नहीं हुआ था लेकिन राष्ट्रीय डोपिंग निरोधक एजेंसी मेरा नमूना कभी भी, कहीं भी ले सकती है। चूंकि यह विश्व एथलेटिक्स से मान्यता प्राप्त स्पर्धा नहीं है तो यह राष्ट्रीय रिकॉर्ड नहीं माना जाएगा लेकिन टूर्नामेंट का रिकॉर्ड है।% लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी की एशियाई चैम्पियन पूजा सिंह ने ऊंची कूद में 1.85 मीटर का टूर्नामेंट रिकॉर्ड बनाकर स्वर्ण पदक जीता।

विराट सबसे अधिक समय तक नंबर एक पर रहने वाले विश्व के तीसरे बल्लेबाज बने

-रिचर्ड्स और लारा है पहले और दूसरे नंबर पर

दुबई (एजेंसी)। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) ने अपने पहले वाले आंकड़े में बदलाव करते हुए कहा है कि भारतीय टीम के अनुभवी बल्लेबाज विराट कोहली अपने करियर में 825 नहीं बल्कि कुल 1,547 दिन नंबर एक बल्लेबाज रहे हैं। इसके साथ ही विराट एकदिवसीय रैंकिंग में सबसे अधिक समय तक शीर्ष पर रहने वाले तीसरे बल्लेबाज बन गये हैं। अब केवल वेस्टइंडीज़ के महान खिलाड़ी विव रिचर्ड्स ही 2,306 दिन और ब्रायन लारा ही 2,079 दिन के साथ ही उनसे आगे हैं। आईसीसी ने अपने ताजा अपडेट में लिखा, 'विराट अक्टूबर 2013 में पहली बार एकदिवसीय बल्लेबाजी रैंकिंग में शीर्ष पर पहुंचे थे और अब तक कुल 1547 दिन नंबर 1 स्थान रहे हैं, ये किसी भी अन्य भारतीय बल्लेबाज से ज्यादा समय है। वहीं विश्व स्तर पर सूची में वह तीसरे नंबर पर हैं, इस सूची में नंबर एक पर वेस्टइंडीज के दिग्गज विवियन रिचर्ड्स हैं, जो 2,306 दिनों तक शीर्ष पर रहे थे जबकि ब्रायन लारा 2,079 दिन के साथ ही दूसरे नंबर पर हैं।' इस बदलाव से अब विराट कई दिग्गज खिलाड़ियों से आगे निकल गए हैं और लंबे समय तक शीर्ष पर रहने के मामले में रिचर्ड्स और लारा के बाद तीसरे नंबर पर आ गए हैं।

बीबीएल में स्टीव स्मिथ का तूफान, 107 मीटर के सिक्स सहित जड़ा रिकॉर्डतोड़ शतक

सिडनी (एजेंसी)। ऑस्ट्रेलिया के स्टार बल्लेबाज स्टीव स्मिथ ने एक बार फिर साबित कर दिया कि वह सिर्फ क्लासिक बल्लेबाज़ ही नहीं, बल्कि आधुनिक टी20 क्रिकेट के सबसे खतरनाक हिटर भी हैं। बिग बैश लीग 2025-26 के सिडनी डर्बी में स्मिथ ने ऐसी पारी खेली जिसने दर्शकों को हैरान और गेंदबाजों को बेबस कर दिया। सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पर थंडर के खिलाफ खेलते हुए, सिक्सर्स के कप्तान ने टूर्नामेंट इतिहास का संयुक्त रूप से दूसरा सबसे तेज़ शतक जड़कर मुकाबले की पूरी कहानी बदल दी।

41 गेंदों में शतक, BBL इतिहास में खास मुकाम

स्टीव स्मिथ ने सिर्फ 41 गेंदों में अपना शतक पूरा किया, जो BBL के इतिहास में संयुक्त रूप से दूसरा सबसे तेज़ शतक है। इससे पहले 2024 में जोश ब्राउन ने भी इतनी ही गेंदों में सेंचुरी बनाई थी। केवल क्रेग सिमंस और मिशेल ओवेन ही ऐसे बल्लेबाज़ हैं जिन्होंने 39 गेंदों में शतक जड़कर स्मिथ से तेज यह उपलब्धि हासिल की है। यह शतक न सिर्फ तेज था, बल्कि स्मिथ के करियर की सबसे आक्रामक पारियों में से एक माना जा रहा है।

107 मीटर का छक्का बना मैच का सबसे बड़ा आकर्षण

मैच का सबसे यादगार पल चौथे ओवर में आया, जब स्मिथ ने नाथन मैकएंड्रयू की गेंद पर फ्रंट फुट हटाकर मिड-विकेट के ऊपर 107 मीटर लंबा छक्का जड़ दिया। यह छक्का पूरे स्टेडियम में चर्चा का विषय बन गया और सोशल मीडिया पर भी तेजी से वायरल हुआ। स्मिथ की फुटवर्क, टाइमिंग और ताकत का यह शानदार मिश्रण गेंदबाजों के लिए चेतावनी बन गया।

सिक्सर्स के लिए सबसे तेज BBL शतक

स्मिथ ने इस पारी के साथ सिडनी सिक्सर्स के लिए सबसे तेज़ BBL शतक का रिकॉर्ड भी अपने नाम किया। उन्होंने 2023 में थंडर के खिलाफ बनाए गए 56 गेंदों के अपने ही पुराने रिकॉर्ड को तोड़ दिया। वह 42 गेंदों में 100 रन बनाकर आउट हुए, जिसमें पांच चौके और नौ गगनचुंबी छक्के शामिल थे। उनकी पारी का अंत लेग स्पिनर तनवीर संघा ने किया।

एक ओवर में 32 रन, BBL का सबसे महंगा ओवर

12वें ओवर में स्मिथ ने रयान हैडली की गेंदों पर 32 रन ठोक दिए, जो BBL इतिहास का सबसे महंगा ओवर बन गया। इस ओवर में उन्होंने तीन छक्के, एक चौका और शानदार टाइमिंग के साथ रन बटोरे। इस ओवर ने मैच को पूरी तरह सिक्सर्स के पक्ष में झुका दिया।

190 रन का लक्ष्य आसानी से हासिल

स्मिथ की विस्फोटक बल्लेबाज़ी की बदौलत सिडनी सिक्सर्स ने 190 रन का लक्ष्य सिर्फ पांच विकेट खोकर हासिल कर लिया। स्मिथ ने मात्र 23 गेंदों में अर्धशतक पूरा कर रन चेज की नींव रखी। बाबर आजम ने 47 रनों की संयमित पारी खेली, जबकि लैचलान शॉ और जैक एडवर्ड्स के छोटे लेकिन अहम योगदान ने जीत को आसान बना दिया। सिक्सर्स ने 16 गेंदें शेष रहते मुकाबला अपने नाम कर लिया।

डेविड वॉर्नर की सेंचुरी गई बेकार

सिडनी थंडर की ओर से डेविड वॉर्नर ने शानदार शतक लगाया और 65 गेंदों में 110 रन बनाए, लेकिन उन्हें दूसरे छोर से कोई ठोस समर्थन नहीं मिला। निक मैडिनसन और सैम बिलिंग्स ने कोशिश की, लेकिन टीम बड़ी साझेदारी नहीं बना सकी। अंत में स्मिथ की विस्फोटक पारी के सामने वॉर्नर की मेहनत फीकी पड़ गई और सिक्सर्स ने सिडनी डर्बी में दबदबे के साथ जीत दर्ज की।

रोजर फेडरर रॉड लेवर एरिना में लौटे, रूड के साथ किया अभ्यास

मेलबर्न। ऑस्ट्रेलियन ओपन में अपनी आखिरी उपस्थिति के छह साल बाद रोजर फेडरर मेलबर्न के कोर्ट पर वापस आ गए हैं। स्विस दिग्गज शुक्रवार को 2020 के बाद पहली बार कैस्पर रूड के साथ प्रैक्टिस सेशन के लिए रॉड लेवर एरिना लौटे। फेडरर ने 2022 में प्रोफेशनल टेनिस से संन्यास ले लिया था, अपने करियर में रूड का सामना सिर्फ एक बार किया था। उनकी एकमात्र लेक्सस हेड2हेड भिड़ंत 2019 में रौलां गैरो के चौथे राउंड में हुई थी, जब फेडरर ने नॉर्वेजियन खिलाड़ी को सीधे सेटों में हराया था। 44 साल के खिलाड़ी ने अपने 20 ग्रैंड स्लैम खिताबों में से छह ऑस्ट्रेलियन ओपन में जीते हैं। टूर्नामेंट में उनका जीत-हार का रिकॉर्ड 102-15 है। उन्होंने आखिरी बार 2020 में मेलबर्न में खेला था, जब वह सेमीफाइनल में आखिरकार चैंपियन बने नोवाक जोकोविच से हार गए थे। फेडरर शनिवार को रॉड लेवर एरिना में टूर्नामेंट के पहले उद्घाटन समारोह के हिस्से के रूप में एक प्रदर्शनी मैच खेलने वाले हैं, जिसमें तीन अन्य एटीपी नंबर 1 क्लब सदस्य भी शामिल होंगे- आंद्रे अगासी, पैट्रिक राफ्टर और लेटन हेविट।

सीएसके ने इस कारण सैमसन को खरीदा : हनुमा

मुम्बई। पिछले काफी समय से भारतीय टीम से बाहर चल रहे बल्लेबाज हनुमा बिहारी ने खुलासा किया है कि संजू सैमसन को चेन्नई सुपरकिंग्स (सीएसके) ने इसलिए टीम में लिया क्योंकि दक्षिण में उनके प्रशंसकों की काफी तादाद है। हनुमा ने कहा कि आईपीएल मालिकों की नजर में ये टूर्नामेंट खेल से कहीं बढ़कर हैं। वे इसमें अपने कारोबारी के फायदे पर भी नजर रखते है। ऐसे में सैमसन को शामिल करना उसके लिए जरुरी थी। सैमसन को ओपनर होने के कारण खरीदने की बातें सही नहीं हैं। इसका कारण है कि सीएसके के पास पहले से ही कई ऐसे बल्लेबाज हैं जो पारी की शुरुआत कर सकते हैं। एक वीडियो में हनुमा ने कहा कि सैमसन के फैनबेस के कारण ही उन्हें लेने का दबाव सीएसके पर पड़ा था। टीमों के इस बात पर काफी ध्यान देते हैं कि एक खिलाड़ी टीम के लिए कितना कारोबार ला सकता है उन्होंने आगे कहा, सैमसन जहां भी मैच खेले जाते हैं, केरल के फैंस वहां पहुंच जाते हैं और उनका हौंसला बढ़ाते हैं। जहां तक ओपनर की बात है सीएसके के पास रुतुराज गायकवाड़ और आयुष म्हात्रे हैं। ऐसे में सैमसन को नंबर 3 पर ही उतारा जाना तय है।

टी20 विश्व कप 2026 : आईसीसी का प्रतिनिधिमंडल कर सकता है बंगलादेश का दौरा

ढाका (एजेंसी)। सात फरवरी से भारत और श्रीलंका में होने वाले टी20 विश्वकप में राष्ट्रीय टीम की भागीदारी को लेकर अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) का प्रतिनिधिमंडल बातचीत के लिए बंगलादेश का दौरा कर सकता है। द डेली स्टार की रिपोर्ट के अनुसार खेल सलाहकार आसिफ नजरुल ने गुरुवार को फॉरेन सर्विस एकेडमी में मीडिया से बातचीत में यह बात कही।

आसिफ नजरुल ने कहा, 'नए अपडेट के अनुसार BCB अध्यक्ष अमीनुल इस्लाम बुलबुल ने मुझे बताया कि चर्चा के लिए ICC की एक टीम बंगलादेश आ सकती है। हमारे रुख में बदलाव की कोई संभावना नहीं है। हम विश्व कप में खेलने के लिए उत्सुक हैं, खासकर श्रीलंका में और मुझे पूरा भरोसा है कि इसका आयोजन करना असंभव नहीं

है।' बंगलादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) के एक अधिकारी ने पुष्टि की कि ICC के साथ बातचीत चल रही है, हालांकि दौरे का समय अभी तय नहीं है।

अधिकारी ने द डेली स्टार को बताया, 'हम बातचीत कर रहे हैं, और एक प्रतिनिधिमंडल आने वाला है, लेकिन सही तारीख तय नहीं हुई है। हम संपर्क में हैं, लेकिन समय तय नहीं है।' यह डेवलपमेंट पिछले मंगलवार को BCB लीडरशिप और ICC के बीच हुई वीडियो कॉन्फ्रेंस के बाद हुआ है।

बैठक के बाद बोर्ड ने सुरक्षा चिंताओं का हवाला देते हुए टूर्नामेंट के लिए भारत न जाने के अपने फैसले को दोहराया और बंगलादेश के मैचों को भारत से बाहर स्थानांतरित करने फिर से अनुरोध किया। हालांकि ICC ने BCB से अपने रुख पर फिर से विचार करने का आग्रह किया, लेकिन बोर्ड अपने रुख पर कायम रहा। हालांकि दोनों पक्ष टूर्नामेंट में बंगलादेश की भागीदारी के बारे में 'संभावित समाधान खोजने' के लिए बातचीत जारी रखने पर सहमत हुए।

एडिलेड इंटरनेशनल : फाइनल में विक्टोरिया म्बोको के साथ खेलेंगी उभरती हुई स्टार मिरर एंड्रीवा

कैनबरा। रूस की मिरर एंड्रीवा एडिलेड इंटरनेशनल के फाइनल में कनाडा की विक्टोरिया म्बोको के साथ खेलेंगी। यह मैच महिला टेनिस टूर में सबसे ज्यादा रैंक वाली टीनएजर खिलाड़ियों के बीच होगा। दुनिया की नंबर 8 एंड्रीवा, जो एडिलेड में तीसरी सीड हैं, ने शुक्रवार को ऑस्ट्रेलियन ओपन वार्म-अप इवेंट के सेमीफाइनल में अपनी हमवतन और डबल्स पार्टनर डायना श्नाइडर को 6-3, 6-2 से हराकर शनिवार के फाइनल में जगह बनाई, जहाँ उनका मुकाबला 17वीं रैंक वाली म्बोको से होगा। यह WTA टूर पर एंड्रीवा (18) और म्बोको (19) के बीच पहला मैच होगा। ये दोनों ही टीनएजर खिलाड़ी फिलहाल दुनिया की टॉप 25 महिला खिलाड़ियों में शामिल हैं। एंड्रीवा ने एडिलेड में अपने तीनों मैचों में एक भी सेट नहीं हारा है और हर मैच में उनकी सर्विस सिर्फ एक बार टूटी है। शुक्रवार को रूसी खिलाड़ी ने श्नाइडर की तुलना में नौ ज़्यादा विनर्स लगाए और 10 कम अनफोर्स्ड एरर किए, जो फिलहाल दुनिया में 23वें स्थान पर हैं। कनाडा की विक्टोरिया म्बोको ने स्ट्रेलिया की किम्बर्ली बिरेल को सीधे सेटों में हराकर एडिलेड इंटरनेशनल के फाइनल में जगह बनाई। वर्ल्ड नंबर 17 म्बोको ने ऑस्ट्रेलियन ओपन वार्म-अप इवेंट के सेमीफाइनल में अपना दबदबा बनाया और सिर्फ 59 मिनट में 6-2, 6-1 से जीत हासिल की। एंड्रीवा शनिवार के फाइनल में अपने चौथे डब्ल्यूटीए टूर सिंगल्स खिताब के लिए खेलेंगी, जबकि म्बोको अपने तीसरे खिताब के लिए खेलेंगी।

महिला क्रिकेट में बदलाव की मांग : न्यूजीलैंड की क्रिकेटर ने फील्डिंग नियमों और बाउंड्री साइज पर उठाए सवाल

नई दिल्ली (एजेंसी)। महिला क्रिकेट तेजी से बदल रहा है। खेल की रफ्तार, खिलाड़ियों की ताकत और दर्शकों की दिलचस्पी तीनों में जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है। इसी बदलते परिदृश्य के बीच न्यूजीलैंड की कप्तान और अनुभवी ऑलराउंडर सोफी डिवाइन ने मौजूदा फील्डिंग नियमों और बाउंड्री के आकार को लेकर अहम सवाल खड़े किए हैं। उनका मानना है कि वर्तमान परिस्थितियां बल्लेबाजों के पक्ष में अत्यधिक झुकी हुई हैं, जिससे गेंदबाजों के लिए संतुलन बनाना मुश्किल हो गया है। डिवाइन की यह टिप्पणी महिला क्रिकेट में संभावित सुधारों पर एक नई बहस को जन्म दे सकती है।

फील्डिंग नियमों पर दोबारा विचार की जरूरत

फिलहाल महिला क्रिकेट में नॉन-पावरप्ले ओवरों के दौरान इनर सर्कल के बाहर सिर्फ चार फील्डर रखने की अनुमति है। यह नियम ज्यादा रन और बाउंड्री को बढ़ावा देने के उद्देश्य से लागू किया गया था। हालांकि, सोफी डिवाइन का मानना है कि खेल अब उस स्तर तक पहुंच चुका है जहां इस नियम की समीक्षा जरूरी हो गई है। डिवाइन के अनुसार, बल्लेबाजों की पावर और शॉट-मेकिंग क्षमता में जिस तरह का इजाफा हुआ है, उसे देखते हुए बाहर पांच फील्डर रखने की इजाजत देने से खेल की प्रतिस्पर्धा पर कोई नकारात्मक असर नहीं पड़ेगा।

छोटी बाउंड्री से गेंदबाजों पर बढ़ता दबाव

महिला प्रीमियर लीग (WPL) में बाउंड्री की अधिकतम लंबाई 60 मीटर तय की गई है, जबकि पुरुष क्रिकेट में यह दूरी 70 से 77 मीटर तक होती है। डिवाइन का मानना है कि छोटी बाउंड्री और सीमित फील्डिंग विकल्पों का मेल गेंदबाजों के लिए मुश्किलें बढ़ा देता है। उन्होंने कहा कि खासकर सपाट पिचों पर गेंदबाजों के पास गलती की गुंजाइश बेहद कम रह जाती है, क्योंकि हल्की सी चूक भी आसानी से बाउंड्री में तब्दील हो जाती है।

अमन मोखाड़े ने रचा इतिहास, लिस्ट ए क्रिकेट में सबसे तेज 1000 रन बनाने वाले भारतीय बने

बेंगलुरु (एजेंसी)। विदर्भ के 24 साल के ओपनर अमन मोखाड़े के लिस्ट ए क्रिकेट में सबसे तेज 1000 रन बनाने वाले भारतीय बनने का इतिहास रचने के बाद क्रिकेट की दुनिया में हलचल मच गई है। सिर्फ 16 इनिंग्स में यह उपलब्धि हासिल करते हुए मोखाड़े ने देवदत्त पडिक्कल और अभिनव मुकुंद के 17 इनिंग्स के पिछले भारतीय रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया। उनकी इस उपलब्धि ने साउथ अफ्रीकी लीजेंड ग्रीम पोलक के लंबे समय से चले आ रहे विश्व रिकॉर्ड की भी बराबरी कर ली।

मोखाड़े की रिकॉर्ड तोड़ने वाली पारी 2025-26 विजय हजारे ट्रॉफी के कर्नाटक के खिलाफ एक हाई-प्रेशर सेमीफाइनल में आई। 281 रनों का पीछा करते हुए विदर्भ को शुरुआती झटका लगा जब ओपनर अथर्व तायडे सस्ते में आउट हो गए। मोखाड़े ने शुरुआती दबाव झेला, पहले ध्रुव शौरी के साथ 99 रन की पार्टनरशिप करके चेज को संभाला, जिन्होंने 47 रन बनाए। फिर उन्होंने आर समर्थ के साथ मिलकर तीसरे विकेट के लिए मैच जीतने वाली 147 रन की पार्टनरशिप की।

समर्थ ने 76 रन बनाए, जबकि मोखाड़े ने पारी को संभाला, भले ही ऐंठन की वजह से वह धीमे पड़ रहे थे। कर्नाटक ने पहले बैटिंग करने का फैसला करके 280 रन बनाए थे। उनकी इनिंग में विदर्भ को शुरुआती ब्रेकथ्रू मिले, क्योंकि दोनों ओपनर, मयंक अग्रवाल और पडिक्कल, पहले 10 ओवर के अंदर आउट हो गए। करुण नायर और ध्रुव प्रभाकर के बीच 54 रन की पार्टनरशिप ने कुछ ऑर्डर वापस लाया, इसके बाद करुण नायर और केएल श्रीजीत के बीच 113 रन की पार्टनरशिप हुई।

दोनों ने फिफ्टी पूरी की, लेकिन कर्नाटक ने आखिरी ओवरों में मोमेंटम खो दिया। विदर्भ के बॉलर दर्शन नलकांडे ने बॉल से कमाल किया, उन्होंने 48 रन देकर 5 विकेट लिए। इस सीज़न में घरेलू टूर्नामेंट में मोखाड़े का लगातार अच्छा प्रदर्शन शानदार रहा है। रणजी ट्रॉफी के पहले लेग में उन्होंने 7 इनिंग में 96.16 की एवरेज से 577 रन बनाए। वह 2025-26 सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में 157.25 की स्ट्राइक रेट से 206 रन बनाकर विदर्भ के चार्ट में टॉप पर रहे और विजय हजारे ट्रॉफी में नौ इनिंग में 97.62 की एवरेज से 781 रन बनाकर अपना दबदबा बनाए रखा। इन टूर्नामेंट में, मोखाड़े ने आठ सेंचुरी और पांच हाफ-सेंचुरी लगाई हैं।

भारत ने अंडर-19 विश्वकप क्रिकेट में जीत से शुरुआत की, पहले ही मैच में यूएसए को 6 विकेट से हराया

बुलवायो। भारतीय टीम ने जिम्बाब्वे और नामीबिया में खेले जा रहे अंडर-19 विश्वकप क्रिकेट में जीत के साथ शुरुआत की है। आयुष म्हात्रे की कप्तानी में भारतीय टीम ने अपने पहले ही मैच में संयुक्त राज्य अमेरिका (यूएसए) को 6 विकेट से हरा दिया। बारिश से बाधिम इस मैच में अमेरिकी टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 107 रन बनाये। इसके बाद भारतीय टीम को जीत के लिए 37 ओवरों में 96 रनों का संशोधित लक्ष्य मिला। जो भारतीय टीम ने 17.2 ओवर में ही 4 विकेट के नुकसान पर हासिल कर लिया। अब भारतीय टीम शनिवार को बांग्लादेश से खेलेगी। वहीं भारत के अलावा वेस्टइंडीज, स्कॉटलैंड और जिम्बाब्वे की टीमें भी जीत के साथ ही 2-2 अंक हासिल करने में सफल रही हैं। वेस्टइंडीज अंडर-19 टीम ने तंजानिया को हराया। वहीं जिम्बाब्वे और स्कॉटलैंड का मैच बारिश के कारण नहीं हो पाया।

Web site : www.krantisamay.com & epaper.krantisamay.com www.facebook.com/krantisamay1 www.twitter.com/krantisamay1

संक्षिप्त समाचार

बांग्लादेश में आम चुनाव से पूर्व रोकी गई आगमन वीजा सेवा

ढाका, एजेंसी। बांग्लादेश ने 15 जनवरी से 15 फरवरी तक देश में आगमन वीजा जारी करने की सेवा अस्थायी रूप से बंद कर दी है। यह निर्णय देश में आगामी आम चुनाव और जनमत संग्रह को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। बांग्लादेश पड़ोसी देशों जैसे भूटान-नेपाल के लोगों को आमतौर पर आगमन वीजा की सुविधा देता रहा है, लेकिन अब इस सुविधा को आधिकारिक रूप से स्थगित कर दिया गया है और संबंधित देशों की सरकारों को इस बारे में सूचित कर दिया गया है। एक वरिष्ठ बांग्लादेशी अधिकारी ने अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस के हवाले से बताया कि इस एक महीने की अवधि में सभी देशों के नागरिक, जिन्हें आमतौर पर आगमन पर वीजा मिलता था, उसे प्राप्त नहीं कर सकेंगे। हालांकि, इस फैसले का स्पष्ट कारण अभी तक अंतरिम सरकार ने नहीं बताया है, लेकिन इसे आगामी राष्ट्रीय संसदीय चुनाव और जनमत संग्रह से जोड़ा जा रहा है। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने सुरक्षा उपायों को सख्त करने और चुनावी हिंसा को रोकने के उद्देश्य से आगमन वीजा स्थगित करने का कदम उठाया है।

पाकिस्तान में अलग-अलग ऑपरेशन में 7 आतंकवादी मारे गए

इस्लामाबाद, एजेंसी। पाकिस्तानी सुरक्षा बलों ने पिछले 48 घंटों में दो अलग-अलग इंटेलिजेंस-आधारित ऑपरेशन में सात आतंकवादियों को मार गिराया है। काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट ने बताया कि बुधवार को खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के डेरा इस्माइल खान जिले में किए गए एक ऑपरेशन में तीन आतंकवादी मारे गए। काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट ने विश्वसनीय इंटेलिजेंस पर कार्रवाई करते हुए तीन आतंकवादियों को मार गिराया, जो पुलिस और सुरक्षा बलों पर हमलों में सीधे तौर पर शामिल थे। मारे गए लोगों के पास से तीन कलाश्निकोव राइफल, नौ मैगज़ीन, दो हैंड ग्रेनेड और बड़ी मात्रा में गोला-बारूद बरामद किया गया। सेना ने बताया कि सोमवार को अशांत बलूचिस्तान प्रांत में एक इंटेलिजेंस-आधारित ऑपरेशन के दौरान चार आतंकवादी अलग से मारे गए। सेना की मीडिया विंग, इंटर-सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस ने बताया कि यह ऑपरेशन कलात जिले में किया गया था। सुरक्षा बलों ने आतंकवादियों के ठिकाने पर प्रभावी ढंग से हमला किया और 'तीव्र गोलीबारी' के बाद उनमें से चार को मार गिराया।

उत्तर-पश्चिमी कैमरून में हथियारबंद लोगों ने 15 लोगों को मार डाला

याउंडे , एजेंसी। उत्तर-पश्चिमी कैमरून में एक हमले में हथियारबंद लोगों ने कम से कम 15 लोगों को मार डाला, जिनमें आठ बच्चे भी शामिल थे। स्थानीय प्रमुख टाटा न्ज़िशोटो ने एसोसिएटेड प्रेस को बताया कि यह हमला सुबह-सुबह गिडाडो में हुआ, जो संघर्षग्रस्त उत्तर-पश्चिमी इलाके के दूरदराज के न्दू क्षेत्र में है। कैमरून के पश्चिमी क्षेत्रों में 2017 से लड़ाई चल रही है, जब अंग्रेजी बोलने वाले अलगाववादियों ने फ्रेंच बोलने वाले बहुमत से अलग होने के मकसद से विद्रोह शुरू किया था। उनका मकसद एक स्वतंत्र अंग्रेजी बोलने वाला राज्य बनाना है।

कजाखस्तान में हादसे में भारतीय छात्रा की मौत

अस्ताना, एजेंसी। कजाखस्तान में हुए भीषण सड़क हादसे में एक भारतीय छात्रा की मौत हो गई और दो अन्य घायल हो गए। भारतीय दूतावास ने कहा, मृत छात्रा की पहचान मिली मोहन (25) के रूप में हुई है, जो सेमे मेडिकल यूनिवर्सिटी में पढ़ती थीं। हादसे में आशिका संतोष और जेसीना बी घायल हैं।

ग्रोक नाबालिगों की आपत्तिजनक तस्वीरें बनाता है मुझे इसकी जानकारी नहीं : मस्क

वाशिंगटन, एजेंसी। अरबपति उद्यमी एलन मस्क ने कहा कि एआई चैटबॉट ग्रोक नाबालिगों की आपत्तिजनक या नग्न तस्वीरें बनाता है इस तरक की किसी भी घटना की उन्हें जानकारी नहीं है। मस्क का यह बयान ऐसे समय आया है, जब ग्रोक को लेकर दुनिया भर में जांच और आलोचना तेज होती जा रही है। सोशल मीडिया पोस्ट पर दिए गए बयान में मस्क ने कहा कि ग्रोक को अवैध अनुरोधों को अस्वीकार करने के लिए प्रोग्राम किया गया है। उसे हर देश या राज्य के कानूनों का पालन करना होता है। उन्होंने स्पष्ट किया कि ग्रोक अपने आप कोई तस्वीर नहीं बनाता, बल्कि केवल उपयोगकर्ता के अनुरोध पर ही ऐसा करता है। बता दें कि ग्रोक और एक्स को लेकर वैश्विक स्तर पर दबाव बढ़ रहा है।

पालक पनीर की खुशबू पर विवाद, अमेरिकी यूनिवर्सिटी के खिलाफ भारतीय छात्रों की जीत

वॉशिंगटन, एजेंसी। अमेरिका में पढ़ाई कर रहे भारतीय छात्रों के साथ भेदभाव का एक मामला अब अंतरराष्ट्रीय बहस का विषय बन गया है। भारतीय पीएचडी छात्र आदित्य प्रकाश और उर्मि भट्टाचार्य ने अमेरिका की यूनिवर्सिटी ऑफ़ कोलोराडो बोल्डर के खिलाफ नस्लीय भेदभाव और प्रताड़ना का आरोप लगाते हुए कानूनी लड़ाई लड़ी। यह मामला एक साधारण से दिखने वाले लंच विवाद से शुरू हुआ, लेकिन आखिरकार 1.8 करोड़ रुपये के नागरिक अधिकार समझौते पर जाकर खत्म हुआ।

यह पूरा मामला सितंबर 2023 का है, जब आदित्य प्रकाश ने यूनिवर्सिटी के विभागीय किचन में माइक्रोवेव में अपना खाना गर्म किया। बताया गया कि उस दिन उनके खाने में पालक पनीर था। इसी दौरान एक स्टाफ सदस्य ने कथित तौर पर खाने की खुशबू को लेकर शिकायत करते हुए उनसे माइक्रोवेव का इस्तेमाल न करने को कहा। आदित्य ने जवाब दिया कि यह सिर्फ खाना है, वह उसे गर्म कर रहे हैं और तुरंत चले जाएंगे। यहीं से विवाद ने तूल पकड़ लिया।

आरोप : आदित्य और उर्मि का कहना है कि इस घटना के बाद हालात तेजी से बिगड़ते चले गए। आदित्य को बार-बार वरिष्ठ फैकल्टी के सामने बुलाया गया और कहा गया कि उनकी वजह से स्टाफ 'असुरक्षित' महसूस कर रहा है। वहीं उर्मि भट्टाचार्य को बिना किसी स्पष्ट कारण के अपनी टीचिंग असिस्टेंट की नौकरी से हटा दिया गया। उर्मि का आरोप है कि उन्हें दो दिन लगातार भारतीय खाना खाने के बाद 'दंगा भड़काने' जैसे गंभीर आरोपों का सामना करना पड़ा।

भेदभाव और प्रतिशोध के अहम बिंदु : दो साल तक चली इस कानूनी लड़ाई के बाद सितंबर 2025 में यूनिवर्सिटी ने समझौते पर सहमति जताई। दोनों छात्रों को कुल 1.8 करोड़ रुपये (दो लाख डॉलर) का भुगतान किया गया। आदित्य और उर्मि को मास्टर डिग्री प्रदान की गई। हालांकि, उन्हें भविष्य में यूनिवर्सिटी में पढ़ाई या नौकरी से वंचित कर दिया गया। यूनिवर्सिटी ने किसी भी तरह की कानूनी जिम्मेदारी स्वीकार नहीं की।

किचन नियमों पर भी उठे सवाल : छात्रों ने अपने मुकदमे में यह भी कहा कि विभागीय किचन के नियम खासतौर पर दक्षिण एशियाई समुदाय को निशाना बनाते हैं। उनका दावा था कि इन नियमों के कारण भारतीय और अन्य एशियाई छात्रों को साझा जगहों पर अपना खाना खोलने से हतोत्साहित किया जाता है। यह रवैया सीधे तौर पर नस्लीय भेदभाव की श्रेणी में आता है।

कानूनी लड़ाई और समझौते के बाद : समझौते के बाद यह दंपत्ती भारत लौट आया। उर्मि भट्टाचार्य ने इंस्टाग्राम पर अपनी पीड़ा साझा करते हुए लिखा कि यह लड़ाई सिर्फ खाने की आजादी की नहीं थी, बल्कि सम्मान और आत्मसम्मान की भी थी। उन्होंने कहा कि इस दौरान उन्हें मानसिक और शारीरिक परेशानियों का सामना करना पड़ा, लेकिन वह अन्याय के सामने झुकने वाली नहीं हैं। सोशल मीडिया पर इस फैसले का जोरदार स्वागत हुआ। कई लोगों ने इसे सही तरीके से आवाज उठाने की मिसाल बताया, तो कुछ ने मजाकिया अंदाज में कहा कि वे इस जीत का जश्न और ज्यादा पालक पनीर खाकर मनाएंगे।

ताइवान के पास चीनी सैन्य गतिविधि बढ़ी, पीएलए के नौ लड़ाकू विमान और 11 युद्धपोत ट्रैक किए गए

ताइपे, एजेंसी। ताइवान और चीन के बीच जारी तनाव के बीच एक बार फिर चीनी सेना की गतिविधियों में इजाफा देखा गया है। ताइवान के रक्षा मंत्रालय ने बताया कि उसने अपने क्षेत्र के आसपास पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के 9 लड़ाकू विमानों और 11 चीनी नौसैनिक जहाजों की मौजूदगी दर्ज की है।

विमानों ने मध्य रेखा पार की : ताइवान के रक्षा मंत्रालय के अनुसार, इन सभी 9 विमानों ने मध्य रेखा को पार किया और ताइवान के उत्तरी, दक्षिण-पश्चिमी और पूर्वी एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन में प्रवेश किया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जानकारी साझा करते हुए कहा आज सुबह 6 बजे तक ताइवान के आसपास 9 पीएलए विमान और 11 पीएलएएन जहाजों की गतिविधि दर्ज की गई। सभी विमानों ने मध्य रेखा पार की। स्थिति पर नजर रखी गई और उचित प्रतिक्रिया दी गई।

देश की संप्रभुता की रक्षा करेंगे- राष्ट्रपति लाई चिंग-ते : गौरतलब है कि इससे एक दिन पहले बुधवार को भी ताइवान ने 20 पीएलए विमानों और 9 चीनी युद्धपोतों की मौजूदगी दर्ज की थी, जिनमें से 17 विमानों ने एडीआईजेड में प्रवेश किया था। इससे क्षेत्र में सैन्य दबाव लगातार बढ़ता दिख रहा है। इस बीच, ताइवान के राष्ट्रपति लाई चिंग-ते ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि वह देश की संप्रभुता की रक्षा करेंगे और चीन को ताइवान के मामलों में दखल देने की अनुमति नहीं दी जाएगी। उन्होंने कहा मैं देश की सुरक्षा सुनिश्चित करूंगा और किसी भी तरह के चीनी दबाव को ताइवान तक पहुंचने नहीं दूंगा।

राष्ट्रपति लाई ने यह भी कहा कि चीन द्वारा ताइवान पर बनाया जा रहा दबाव इस बात का प्रमाण है कि बीजिंग का अधिकार ताइवान तक नहीं फैलता और ताइवान, पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना का हिस्सा नहीं है। हाल ही में चीन द्वारा प्रतिबंधित जापानी सांसद हेई सेकी की ताइवान यात्रा का जिक्र करते हुए राष्ट्रपति लाई ने कहा कि यह दौरा इस बात का सबूत है कि रिपब्लिक ऑफ चाइना और पीआरसी एक-दूसरे के अधीन नहीं हैं।

देउबा युग का अंत, गगन थापा बने नेपाली कांग्रेस के नए अध्यक्ष

काठमांडू, एजेंसी। नेपाली कांग्रेस के दूसरे विशेष महाधिवेशन ने गगन थापा के नेतृत्व में नई केंद्रीय कार्यसमिति का सर्वसम्मति से चयन किया है। विशेष महाधिवेशन से गगन थापा पार्टी अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं। इसी तरह, विश्वप्रकाश शर्मा और पुष्पा भुसाल को उपाध्यक्ष चुना गया है। वहीं, महासचिव पद पर गुरु घिमिरे और प्रदीप पौडेल निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। कांग्रेस ने 13 पदाधिकारी और 1 सय 21 केन्द्रीय सदस्य निर्वाचित किया है। इसी के साथ शेर बहादुर देउबा युग का अंत हो गया है। देउबा नेपाली कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष के साथ ही नेपाल के तीन बार प्रधानमंत्री रहे हैं। देउबा 1995 से 1997, 2001 से 2002 तक, और 2004 से 2005 तक नेपाल के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। इससे पहले नेपाली कांग्रेस के विशेष महाधिवेशन समर्थक खेमा गगन थापा को ही पार्टी का नया अध्यक्ष मानकर चल रहा था। दरअसल अध्यक्ष पद के लिए केवल थापा का ही नामांकन होने के कारण इसकी संभावना प्रबल हो गई थी। नेपाली कांग्रेस के विशेष महाधिवेशन समर्थकों ने मंगलवार को ही निर्वाचन आयोग को पत्र भेजकर महाधिवेशन की जानकारी दी। वहीं, देउबा पक्ष विशेष महाधिवेशन को अवैध बता रहा था।

बुल्गारिया में निष्पक्ष चुनाव की मांग, ठंड में उतरे हजारों लोग सड़कों पर : सोफिया , एजेंसी। बुल्गारिया की राजधानी सोफिया में बुधवार को कड़ाके की ठंड के बावजूद हजारों लोग सड़कों पर उतरे और निष्पक्ष चुनाव की मांग की। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि देश लगातार राजनीतिक अस्थिरता से जूझ रहा है और पांच साल में आठवीं बार चुनाव की आशंका है। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि पिछली सरकार ने चुनाव में गड़बड़ी, वोट खरीद और नतीजों में हेरफेर की कोशिशें कीं। मशीन वोटिंग लागू न करने के फैसले पर भी सवाल उठे। राष्ट्रपति रूमेन रादेव सरकार गठन में नाकाम रहने के बाद कार्यवाहक सरकार और नए चुनाव की तैयारी कर रहे हैं।

ईरान और अमेरिका में कभी भी छिड़ सकती है जंग

तेहरान, एजेंसी। क्या अमेरिका और ईरान के बीच जंग होने वाली है? यह सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि पश्चिम एशिया में फिलहाल हालात ऐसे ही बनते दिख रहे हैं। अमेरिका और ब्रिटेन की ओर से अपने नागरिकों को ईरान न जाने की सलाह दी गई है। इसके अलावा ईरान ने अपना एयरस्पेस कमर्शल फ्लाइट्स के लिए बंद कर दिया है। इससे साफ है कि दोनों तरफ से सतर्कता बरती जा रही है और तनाव को देखते हुए जंग की आशंका बढ़ गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप तो लगातार ईरान को जंग और सैन्य कार्रवाई की धमकी दे रहे हैं। वहीं ईरान का कहना है कि ऐसी किसी भी स्थिति में जो आग भड़केगी वह पूरे इलाके को चपेट में लेगी।

वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति के हवाले से एनसीबी न्यूज ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि ट्रंप लंबी जंग नहीं चाहते हैं। उन्होंने अपने सुरक्षा सलाहकारों से ईरान के खिलाफ ऐसे ऐक्शन पर विचार करने को कहा है, जिससे एक निर्णायक कदम उठाया जा सके। वह नहीं चाहते कि ईरान के खिलाफ महीनों लंबी जंग चले। ऐसे में संभावना है कि अचानक ही ईरान पर कोई बड़ा अटैक हो सकता है। अमेरिकी नहीं चाहता कि वह ईरान के खिलाफ किसी भी तरह के जमीनी संघर्ष में शामिल हो। हालांकि अमेरिकी सलाहकार इस बात को लेकर आश्वस्त नहीं हैं कि किसी एक हमले से ईरान की कमर तोड़ी जा सकती है।

उनकी चिंता यह है कि ईरान भी हमले का जवाब देगा और मिडल ईस्ट में अमेरिकी ठिकानों को नुकसान पहुंच सकता है। इराक, सीरिया समेत कई देशों में अमेरिका के ठिकाने हैं, जो ईरान के टारगेट में आ सकते हैं। इसके अलावा ईरान को जवाब देने के लिए इस इलाके में अमेरिका के पास बहुत ज्यादा एसेट्स भी नहीं हैं। इस बीच खबर है कि ट्रंप प्रशासन की ओर से छोटे और टारगेट अटैक किए जा सकते हैं। इसके बाद यदि ईरान की प्रतिक्रिया आती है तो फिर जवाबी कार्रवाई की जाएगी। अमेरिका यह नहीं चाहता कि वह खुद बड़ा अटैक करे। ऐसी स्थिति में ईरान को थोड़ा उकसाने के बाद ही संघर्ष शुरू करने की तैयारी है।

ब्राजील के राष्ट्रपति ने वेनेजुएला मुद्दे पर पुतिन से की बात

ब्रासीलिया , एजेंसी। ब्राजील के राष्ट्रपति लुइज इनासियो लूला दा सिल्वा ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से फोन पर बातचीत की। दोनों नेताओं ने वेनेजुएला की स्थिति और लैटिन अमेरिका में बढ़ते तनाव पर चर्चा की। क्रेमलिन के अनुसार, दोनों देशों ने वेनेजुएला की संप्रभुता और राष्ट्रीय हितों के समर्थन पर सहमति जताई। साथ ही संयुक्त राष्ट्र और ब्रिक्स जैसे मंचों पर मिलकर तनाव कम करने के प्रयास जारी रखने का फैसला किया गया।

मादुरो शासन में बंद कैदियों की रिहाई जारी रहेगी : काराकास, एजेंसी। वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने कहा है कि पूर्व राष्ट्रपति निकोलस मादुरो के दौर में हिरासत में लिए गए कैदियों की रिहाई की प्रक्रिया जारी रहेगी। उन्होंने इसे देश में नए राजनीतिक दौर की शुरुआत बताया। मानवाधिकार संगठनों के मुताबिक अब तक कम से कम 68 कैदियों को रिहा किया जा चुका है। यह कदम अमेरिका की शर्तों को पूरा करने और अंतरराष्ट्रीय दबाव कम करने की दिशा में अहम माना जा रहा है।

ग्रीनलैंड पर अड़ा अमेरिका, नाटो में तनाव; स्थानीय लोगों का ट्रंप को जवाब- यह द्वीप बिकाऊ नहीं : वाशिंगटन, एजेंसी। ग्रीनलैंड की बर्फीली सड़कों पर इन दिनों भारी तनाव है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस द्वीप पर नियंत्रण करना चाहते हैं। उनकी इस जिद ने एक भू-राजनीतिक तूफान खड़ा कर दिया है। डेनमार्क के प्रधानमंत्री ने चेतावनी दी है कि यह विवाद नाटो के अंत का कारण बन सकता है। वहीं, ग्रीनलैंड की राजधानी नूक में रहने वालों ने साफ कह दिया है कि उनका देश बिकाऊ नहीं है।

नई इस्त्राइली फिल्म निर्भया कांड की रैलियों से प्रेरित; निर्माता बोले- उस समय भारत की यात्रा पर था : तेल अवीव , एजेंसी। निर्भया कांड के बाद देशभर में उठे जनआक्रोश ने अब अंतरराष्ट्रीय सिनेमा को भी प्रभावित किया है। इस्त्राइली फिल्म निर्माता डैन वोलमैन की नई फिल्म भारत की उस त्रासदी और उसके खिलाफ हुए प्रदर्शनों से प्रेरित है। आइए जानते हैं फिल्म निर्माता ने इस पर क्या कुछ कहा। इस्त्राइली फिल्म निर्माता डैन वोलमैन ने नई फिल्म मर्डर्स टू क्लोज, लव टू फार में भारतीय फिल्म निर्माता मंजू बोरा के साथ मिलकर 2012 में हुए निर्भया दुष्कर्म और उसकी हत्या के घटनाक्रम पर बनाई है। वोलमैन ने कहा, वह जब 2012 में भारत यात्रा पर आए, तब दिल्ली में एक फिजियोथेरेपी इंटर्न (निर्भया) के साथ हुए सामूहिक दुष्कर्म के विरोध में व्यापक प्रदर्शन हो रहे थे। फिल्म की प्रेरणा उन्हें वहीं से मिली। फ्लोच, माई माइकल, ऐन इस्त्राइली लव स्टोरी और वैली ऑफ स्ट्रेंथ जैसी फिल्मों के लिए मशहूर वोलमैन ने मंजू बोरा के साथ मिलकर इस मर्डर मिस्ट्री का सह-निर्देशन किया है। यह ऐसी पहली फिल्म है जिसका सह-निर्माण भारत और इस्त्राइली फिल्मकारों ने किया है। इसे 24वें पुणे अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव (पीआईएफएफ) में प्रदर्शित किया जाएगा। वोलमैन ने कहा, निर्भया कांड भयावह घटना थी। वोलमैन ने कहा, फिल्म की शूटिंग भारत में हुई है और इसमें यौन उत्पीड़न, हिंसा, भ्रष्टाचार, समूह के व्यवहार, गिरोह और भीड़ की मानसिकता जैसे विषयों को उठाया गया है।

अमेरिकी धमकियों के बीच एक हुए शिया और सुन्नी मुसलमान देश? ईरान को सऊदी अरब से संदेश

तेहरान, एजेंसी। अमेरिका की ओर से ईरान को लगातार हमले की धमकियां दी जा रही हैं। इस बीच इस्लामिक जगत में शिया और सुन्नी मुसलमान देशों के बीच के मतभेद खत्म होते दिख रहे हैं। अमेरिकी हमले की स्थिति में सऊदी अरब ने ईरान को भरोसा दिया है कि वह अपनी जमीन का इस्तेमाल नहीं होने देगा। सऊदी अरब ने ईरान को बताया है कि वह अपनी जमीन का उसके खिलाफ हमलों में इस्तेमाल नहीं होने देगा। यही नहीं वह अपने एयरस्पेस से भी ऐसे किसी लड़ाकू विमान को गुजरने नहीं देगा, जिसका मकसद ईरान पर हमला करना हो। सऊदी अरब की ओर से ईरान को मिला यह भरोसा अहम माना जा रहा है।

वॉशिंगटन से कई बार ईरान को धमकी मिल चुकी है, जिसमें उसने कहा कि यदि प्रदर्शनकारियों पर सख्ती बरती गई तो वह सैन्य हस्तक्षेप करेगा। सऊदी अरब को अमेरिका के करीबी दोस्तों में शुमार किया जाता है। इसके अलावा शिया और सुन्नी विवाद के कारण भी ईरान और सऊदी अरब के बीच एक दूरी रही है। ऐसे में सऊदी अरब की तरफ से ईरान को भरोसा दिया जाना बड़ा संकेत है। खासतौर पर तब जबकि पाकिस्तान समेत किसी भी इस्लामिक देश ने ईरान के साथ एकता की बात नहीं की है। पाकिस्तान अकसर इस्लामिक एकता का राग अलापता रहा है, लेकिन अमेरिकी की ओर से ईरान को मिल रही धमकियों के बाद भी वह चुप है।

अमेरिका के मिडल ईस्ट में कई ठिकाने, सऊदी अरब में भी : सऊदी विदेश मंत्रालय के एक सूत्र ने एएफपी को बताया, 'हमारी ओर से ईरान को स्पष्ट कर दिया गया है कि सऊदी अरब उसके खिलाफ किसी भी अलायंस का हिस्सा नहीं बनेगा। इसके अलावा हम ईरान पर हमले के लिए अपनी जमीन और एयरस्पेस का भी इस्तेमाल नहीं होने देंगे।' अमेरिका के मिडल ईस्ट में कई ठिकाने हैं। इनमें से कुछ सऊदी अरब में भी हैं। माना जाता रहा है कि ईरान और अमेरिका के बीच छिड़ी जंग में सऊदी अरब किसी का पक्ष नहीं लेगा। उसका अब भी ऐसा ही स्टैंड है, लेकिन ईरान को उसने जो भरोसा दिया है, वह अहम है। बता दें कि अमेरिका और ईरान के बीच तनाव इस कदर है कि तेहरान ने एयरस्पेस बंद कर दिया है।

पहली मेडिकल इवैकुएशन में 4 अंतरिक्ष यात्रियों की आईएसएस से धरती पर वापसी; नासा का ऐतिहासिक फैसला

वाशिंगटन, एजेंसी। नासा ने अपने 65 वर्षों के मानव अंतरिक्ष उड़ान इतिहास में पहली बार एक ऐतिहासिक और संवेदनशील फैसला लेते हुए मेडिकल इवैकुएशन के तहत चार अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन से पृथ्वी पर वापस बुला लिया है। यह मिशन तय समय से एक महीने पहले ही समाप्त कर दिया गया।

4 अंतरिक्ष यात्रियों की धरती पर वापसी : नासा, रूस और जापान के इन चार अंतरिक्ष यात्रियों ने बुधवार को स्पेस स्टेशन से विदाई ली और वे स्पेसएक्स कैप्सूल के जरिये गुरुवार तड़के कैलिफोर्निया के सैन डिएगो तट के पास प्रशांत महासागर में उतरने वाले हैं। इस मिशन में शामिल नासा की अंतरिक्ष यात्री जेना कार्डमैन ने भावुक होते हुए कहा हमारी वापसी का समय अचानक बदला, लेकिन सबसे खूबसूरत बात यह रही कि यह टीम एक परिवार की तरह एक-दूसरे का ख्याल रखती रही। हालांकि नासा ने उस अंतरिक्ष यात्री की पहचान उजागर नहीं की, जिसे चिकित्सकीय देखभाल की आवश्यकता थी। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि यात्री की हालत स्थिर और सुरक्षित है तथा यह फैसला पूरी सावधानी के साथ लिया गया है ताकि धरती पर बेहतर मेडिकल जांच संभव हो सके। नासा ने यह भी साफ किया कि यह कोई आपात स्थिति नहीं थी, लेकिन अंतरिक्ष में रहते हुए इलाज में देरी करना जोखिम भरा हो सकता था। इसलिए मिशन को छोटा करने का निर्णय लिया गया।

इस दल में शामिल अंतरिक्ष यात्री: जेना कार्डमैन (अमेरिका)- पहली अंतरिक्ष उड़ान माइक फिन्के (अमेरिका)- अनुभवी अंतरिक्ष यात्री किमिया युई (जापान)- दूसरी अंतरिक्ष यात्रा ओलेग प्लातोनोव (रूस)- पहली अंतरिक्ष उड़ान स्पेस स्टेशन पर फिलहाल एक अमेरिकी और दो रूसी अंतरिक्ष यात्री मौजूद हैं। नासा और स्पेसएक्स अब फ्लोरिडा से नए दल की लॉन्चिंग की तारीख को आगे खिसकाने पर काम कर रहे हैं। नासा के नए प्रशासक जारेड आइजैकमैन ने इस फैसले पर कहा हमारे अंतरिक्ष यात्रियों का स्वास्थ्य और सुरक्षा हमेशा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता रहेगी।

लगभग छह महीने तक चलने वाला मिशन : क्रू-11 को अगस्त 2025 में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन (आईएसएस) के लिए लॉन्च किया गया था, जिसका मिशन मूल रूप से लगभग छह महीने तक चलने वाला था। अधिकारियों ने कहा कि एजेंसी और उसके अंतर्राष्ट्रीय सहयोगी कक्षा में चिकित्सा आपात स्थितियों के लिए नियमित रूप से प्रशिक्षण लेते हैं और जरूरत पड़ने पर प्रतिक्रिया देने के लिए तैयार हैं।

फरवरी 2026 तक रहने की थी उम्मीद : दरअसल, क्रू-11 मिशन, आईएसएस पर निरंतर मानव उपस्थिति बनाए रखने के नासा के सतत प्रयासों का हिस्सा है। अपने प्रवास के दौरान अंतरिक्ष यात्री वैज्ञानिक अनुसंधान, प्रौद्योगिकी प्रदर्शन और स्टेशन के नियमित रखरखाव का कार्य कर रहे हैं। साथ ही भविष्य के मिशनों की तैयारियों में भी सहयोग कर रहे हैं। चालक दल के मध्य फरवरी 2026 तक कक्षा में रहने की उम्मीद थी।

स्वामी,मुद्रक व् प्रकाशकः सुरेश मौर्या द्वारा अष्ठ विनायक ओफ़्सेट एफपी,149 प्लोट 26 खोडीयारनगर,सिद्धिविनायक मंदीर के पास ,भाटेना) हो.सो अंजना सुरत गुजरात से मुद्रित एवं 191 महादेव नगर उधना सुरत गुजरात से प्रकाशित संपादक : सुरेश मौया (M) 9879141480 RNI No.:GUJHIN/2018/75100 (Subject to Surat jurisdiction)

कोर्ट ने ममता बनर्जी को सिखाया सबक, बीजेपी बोली- अब विधानसभा चुनाव में भी हार तय

-आई-पेक रेड मामले में बंगाल सरकार को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस

नई दिल्ली (एजेंसी)। आई-पेक रेड मामले में सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद पश्चिम बंगाल का राजनीतिक गलियारा पूरी तरह से गरमा गया है। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के खिलाफ दर्ज एफआईआर पर रोक लगाए जाने और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी व पुलिस अधिकारियों को नोटिस जारी किए जाने के बाद भाजपा ने तृणमूल कांग्रेस सरकार पर तीखा हमला बोला है। भाजपा विधायक अग्रिमित्रा पॉल ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को अच्छा सबक सिखाया है और उनकी झूठ की राजनीति अब उजागर हो चुकी है।

बीजेपी विधायक पॉल ने आरोप लगाया, कि पिछले 15 वर्षों से टीएमसी सरकार और उससे पहले वाम दलों की सरकार ने रोहिंग्या, बांग्लादेशी घुसपैठियों और फर्जी मतदाताओं के सहारे चुनाव जीते। उन्होंने दावा किया कि इस बार पश्चिम बंगाल में ऐसा नहीं होने दिया जाएगा। पॉल के मुताबिक अब तक करीब 58 लाख नाम मतदाता सूची से हटाए जा चुके हैं और आगे भी यह प्रक्रिया जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पद की गरिमा को ठेस पहुंची है और अब सच्चाई जनता के सामने आ रही है।

दरअसल, गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने आई-पेक रेड मामले में बड़ा आदेश देते हुए ईडी अधिकारियों के खिलाफ दर्ज एफआईआर पर रोक लगा दी। इसके साथ ही कोर्ट ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और संबंधित पुलिस अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। कोर्ट का कहना है कि कानून के शासन को बनाए रखने और केंद्रीय एजेंसियों को स्वतंत्र रूप से काम करने देने के लिए इस मामले की जांच जरूरी है।

ममता खुद भी चुनाव हारने वाली हैं: शहनवाज

भाजपा नेता सैयद शहनवाज हुसैन ने भी सीएम ममता बनर्जी पर हमला बोलते हुए कहा कि मुख्यमंत्री को खुद पता है कि वह 2026 के विधानसभा चुनाव में बुरी तरह हारने वाली हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि जिस तरह राहुल गांधी और तेजस्वी यादव वोट चोरी का मुद्दा उठाकर माहौल बनाते रहे हैं, उसी तरह ममता बनर्जी भी मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) का विरोध कर रही हैं। शहनवाज हुसैन ने दावा किया कि 2026 के विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी की हार तय है और पश्चिम बंगाल में भाजपा की जीत होगी।

यो यो हनी सिंह अश्लील कमेंट्स के बाद आए विवादों में तो मांगी माफी, जस्सी ने जाहिर की नाराजगी

लुधियाना (एजेंसी)। मशहूर सिंगर और रैपर यो यो हनी सिंह फिर विवादों में घिर गए हैं। दो दिन पहले दिल्ली में हुए एक कॉन्सर्ट के दौरान उन्होंने स्टेज से ठंड के बहाने अश्लील बातें कीं, जिससे युवाओं को अनुचित व्यवहार के लिए प्रोत्साहित करने का आरोप लगा। इस दौरान फैंस का वीडियो भी वायरल हुआ। इस घटना के बाद पंजाबी सिंगर

जसबीर जस्सी ने ट्वीट कर अपनी नाराजगी व्यक्त की। जस्सी ने कहा कि हनी सिंह ने सभी हदें पार कर दी हैं और उनकी माता-पिता व बहन से अपील की कि उन्हें रोकना चाहिए, नहीं तो यह आगे बढ़ सकता है और गलत संदेश जाएगा। विवाद बढ़ने पर हनी सिंह ने सार्वजनिक रूप से माफी मांगी। हनी सिंह पहले भी गानों और स्टेज प्रदर्शन में अश्लील डांस और बोल को लेकर विवादों में रह चुके हैं। 2014 से 2018 तक वह म्यूजिक इंडस्ट्री से दूर रहे, जिसे उन्होंने डिप्रेशन, एंग्जाइटी और मानसिक परेशानियों से जोड़कर बताया था। कुछ दिन पहले ही हनी सिंह के एक पुराने गीत को लेकर जालंधर के भाजपा नेता ने डीजीपी को शिकायत दी थी, जिसमें उन्होंने गाने में अश्लीलता और बिकिनी गर्ल्स को लेकर कड़ी आपत्ति जताई थी। यह मामला हनी सिंह के विवादित प्रदर्शन और उनके सामाजिक प्रभाव पर एक बार फिर सवाल खड़ा करता है।

चंडीगढ़ में गौशाला में करीब 50 गायों के क्षत-विक्षत शव मिलने से हड़कंप

चंडीगढ़ (एजेंसी)। चंडीगढ़ में माखन माजरा इलाके के पशु अवशेष निस्तारण केंद्र में करीब 50 गायों के क्षत-विक्षत शव मिलने के बाद प्रशासन ने कड़ा कदम उठाया है। मुख्य सचिव एच. राजेश प्रसाद ने सभी गौशालाओं में 24 घंटे सातों दिन सीसीटीवी निगरानी लागू करने और नियमित समीक्षा सुनिश्चित करने के आदेश दे दिए। पोस्टमॉर्टम और विस्तृत जांच के आदेश दिए गए हैं, जिनकी रिपोर्ट एक सप्ताह में आने की संभावना है। पुलिस ने थाने में अज्ञात लोगों के खिलाफ पशु क्रूरता निवारण अधिनियम की धारा 11 के तहत मामला दर्ज किया। माखन माजरा गौशाला प्रबंधन समिति की शिकायत में बताया गया कि गौवंश को पर्याप्त चारा, पानी, आश्रय और चिकित्सा सुविधा नहीं मिलने के कारण कई जानवर मृत मिले है। 13 जनवरी को निरीक्षण के दौरान 50-60 मृत गायें मिलीं और निरीक्षण के समय किसी पशु चिकित्सक की सुविधा उपलब्ध नहीं थी। मुख्य सचिव ने रायपुर कलां, औद्योगिक क्षेत्र और माखन माजरा की गौशालाओं का निरीक्षण कर और गौवंश एवं पशुओं की देखभाल, स्वच्छता और कल्याण संबंधी व्यवस्थाओं की समीक्षा की। उन्होंने निर्देश दिए कि हर गौशाला में उचित आवास, नियमित भोजन और पेयजल सुनिश्चित करे। इंसिनरेटर की तकनीकी खराबी को तत्काल सुधारने का आदेश दिया। कर्मचारियों और पशु चिकित्सकों की पूरी जानकारी और ड्यूटी रोस्टर प्रमुख स्थान पर प्रदर्शित करने को कहा गया। घटना पर भाजपा नेता संजय टंडन ने 'चौंकाने वाला और अस्वीकार्य' बताया और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की। गौ-रक्षा समूहों ने भी विरोध प्रदर्शन करते हुए मृत बछड़े का शव सड़क पर रखकर गोवध और पशु तस्करी के खिलाफ चेतावनी दी।

विष्णुपुर में पेट्रोल पंप पर बम विस्फोट में शामिल आरोपी गिरफ्तार

इंफाल (एजेंसी)। सुरक्षा बलों ने पिछले सप्ताह मणिपुर के बिष्णुपुर जिले में एक पेट्रोल पंप पर हुए बम विस्फोट में शामिल होने के आरोप में एक और व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने शुक्रवार को जानकारी देते हुए बताया कि 41 साल के आरोपी को गुरुवार को इम्फाल पश्चिम जिले के लैंफेल सना कीथेल इलाके से गिरफ्तार किया और उसके पास से भारी मात्रा में हथियार व गोला-बारूद बरामद किया है। इससे पहले प्रतिबंधित कांगलेई यावोल कन्ना लुप (केवाईकेएल) के 35 साल के एक सदस्य को काकचिंग जिले के कोमनाओ माखा लीकाई इलाके से गिरफ्तार किया था। अधिकारी ने बताया कि 15 जनवरी को गिरफ्तार किया गया व्यक्ति बम विस्फोट के मुख्य आरोपी का सहयोगी है। 8 जनवरी की शाम को मोइरांग थाना लेइकाई इलाके में स्थित एलीडास पेट्रोल पंप पर बम फेंका गया। इस विस्फोट के बाद मणिपुर में घाटी के सभी इलाकों में स्थित पेट्रोप पंप स्टेशनों को तीन दिन के लिए बंद कर दिया गया था।

रापर क्षेत्र में फिर डोली धरती, खेगांरपर के पास 2.5 तीव्रता का भूकंप, लोगों में दहशत

कच्छ (एजेंसी)। गुजरात के सरहदी जिले कच्छ में एक बार फिर धरती के भीतर हलचल दर्ज की गई है। कच्छ के रापर तहसील के खेगांरपर गांव के पास आज तड़के भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप विज्ञान केंद्र (आईएसआर) के अनुसार, सुबह 5-47 बजे रिक्टर स्केल पर 2.5 तीव्रता का भूकंप दर्ज किया गया। भूकंप का केंद्र रापर से लगभग 19 किलोमीटर दूर खेगांरपर के निकट बताया गया है। झटके महसूस होते ही आसपास के इलाकों में रहने वाले लोग घबराकर नींद से जाग गए और एहतियातन घरों से बाहर निकल आए। कुछ समय के लिए क्षेत्र में भय का माहौल बन गया। हालांकि भूकंप की तीव्रता कम होने के कारण किसी भी प्रकार के जान-माल के नुकसान की कोई सूचना नहीं है, लेकिन बार-बार आ रहे भूकंप के झटकों से स्थानीय लोगों की चिंता बढ़ती जा रही है। उल्लेखनीय है कि बीते महीने 26 दिसंबर 2025 को रापर के गेडी गांव के पास 4.4 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप आया था। उस दौरान रापर के साथ-साथ भचाऊ और अंजार तक झटके महसूस किए गए थे। इसके बाद से क्षेत्र में छोटे-बड़े आफ्टरशॉक्स का सिलसिला लगातार जारी है, जिससे लोग सतर्क और चिंतित हैं।

चार मंजिला इमारत में लगी भीषण आग तो लोगों ने कूदकर बचाई जान, आसपास के घर खाली कराए गए

लखनऊ (एजेंसी)। राजधानी लखनऊ के ठाकुरगंज इलाके में शुक्रवार को उस वक्त अफरा-तफरी मच गई, जब बसंत कुंज क्षेत्र में स्थित एक चार मंजिला अपार्टमेंट में भीषण आग लग गई। आग इतनी तेजी से फैली कि देखते ही देखते इमारत की तीन मंजिलें उसकी चपेट में आ गईं। आग की लपटों और घने धुएं से पूरी बिल्डिंग भर गई, जिससे अंदर मौजूद लोगों की जान पर बन आई। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक आग लगते ही अपार्टमेंट में चीख-पुकार मच गई। धुआं इतना घना हो गया कि लोगों को बाहर निकलने का रास्ता तक दिखाई नहीं दे रहा था। जान बचाने के लिए कई लोग बालकनी और खिड़कियों से कूद पड़े। कुछ लोगों को आसपास के लोगों और दमकलकर्मियों की मदद से सुरक्षित बाहर निकाला गया। इस दौरान इलाके में दहशत का माहौल बन गया। आग की सूचना मिलते ही दमकल विभाग की चार गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और आग बुझाने का काम शुरू किया गया। दमकलकर्मी लगातार आग पर काबू पाने की कोशिश में जुटे रहे। मुख्य अग्निशमन अधिकारी (सीएफओ) अंशु मित्तल ने मीडिया को बताया कि आग लगने के दौरान एक युवक बिल्डिंग के अंदर फंस गया था, जिसे दमकलकर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद सुरक्षित बाहर निकाल लिया। उन्होंने बताया कि फिलहाल किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है, लेकिन कुछ लोगों को धुएं के कारण परेशानी हुई है। आग की भयावहता को देखते हुए एहतियातन आसपास के घरों को खाली करा लिया गया। पुलिस और प्रशासन की टीमें भी मौके पर मौजूद रहीं और स्थिति पर नजर बनाए रखा। आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल सका है। शुरुआती आशंका शॉर्ट सर्किट की जताई जा रही है, हालांकि जांच के बाद ही वास्तविक कारण स्पष्ट हो पाएगा।

बीजेपी सरकार ने मतदाता सूचियों में हेराफेरी का जो षड्यंत्र रचा है, वह शर्मनाक: गहलोत

जयपुर (एजेंसी)। पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने राजस्थान की बीजेपी सरकार पर प्रशासन का दुरुपयोग कर मतदाता सूचियों में हेराफेरी का षड्यंत्र रचने का आरोप लगाया है। गहलोत ने कहा कि आज का दिन राजस्थान में लोकतंत्र के लिए काले अध्याय जैसा है, जिसने बीजेपी को बेनकाब कर दिया है। सत्ता के मद में चूर बीजेपी सरकार ने प्रशासन का दुरुपयोग कर मतदाता सूचियों में हेराफेरी का जो षड्यंत्र रचा है, वह शर्मनाक है।

पूर्व सीएम गहलोत ने दावा किया कि मतदाता सूची के एसआईआर प्रक्रिया के अंतिम दिन एक सुनियोजित साजिश के तहत निर्वाचन पंजीकरण अधिकारियों के जरिए बीएलओ पर दबाव डाला गया कि वे कांग्रेस विचारधारा वाले मतदाताओं के नाम काट दें। उन्होंने आरोप लगाया कि यहां तक कि फॉर्म-सात में पहले से डेटा भरकर बीएलओ को सौंपा गया, जो निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया पर सीधा हमला है। उन्होंने कहा कि कई जगहों पर प्रशासनिक अधिकारियों और बीएलओ ने इस लोकतंत्र की हत्या में शामिल होने से इनकार किया है, तो सत्ताधारी पार्टी के लोगों ने उन्हें तबादलों की धमकी दी है।

गहलोत ने कहा कि बीजेपी ने ऐसा दुस्साहस कर जनता और लोकतंत्र का अपमान किया है। मेरे निर्वाचन क्षेत्र सरदारपुरा तक में ऐसा कुप्रयास किया गया है। मैंने इस संबंध में राज्य निर्वाचन आयुक्त नवीन महाजन से फोन पर बात कर जानकारी दी है और त्वरित कार्रवाई की मांग की है।

उन्होंने निर्वाचन कार्य में लगे अधिकारियों से संवैधानिक मर्यादा का पालन करने की अपील की। गहलोत ने कहा कि मैं उन अधिकारियों को भी स्पष्ट शब्दों में आगाह करना चाहता हूं जो बीजेपी के दबाव में संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं। समय बदलते देर नहीं लगती। सरकारें आती-जाती रहेंगी, लेकिन यदि आपने नियम विरुद्ध कार्य किया तो कानून के दायरे में आपकी जवाबदेही सुनिश्चित की जाएगी और सख्त कार्रवाई होगी। उन्होंने कहा कि संवैधानिक मर्यादा का पालन करें, अन्यथा परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहें।

ऑपरेशन स्वदेश: ईरान से भारतीयों को एयरलिफ्ट कर स्वदेश ला रही सरकार

-पहली विशेष फ्लाइट तेहरान से दिल्ली आज आएगी

नई दिल्ली (एजेंसी)। ईरान में जारी सरकार विरोधी हिंसक प्रदर्शनों और अस्थिर हालात को देखते हुए केंद्र सरकार ने वहां फंसे भारतीय नागरिकों की सुरक्षित वापसी को लेकर 'ऑपरेशन स्वदेश' शुरू कर दिया है। इस अभियान के तहत पहली विशेष फ्लाइट आज शुक्रवार को तेहरान से नई दिल्ली पहुंच रही है। विदेश मंत्रालय ने इस बात की पुष्टि करते हुए कहा है, कि रेस्क्यू ऑपरेशन को चरणबद्ध तरीके से अंजाम दिया जाएगा।

ईरान में इस समय लगभग 10 हजार भारतीय नागरिक मौजूद हैं। इनमें छात्र, कारोबारी, तकनीकी विशेषज्ञ और अन्य पेशेवर शामिल हैं। इनमें से करीब 2500 से 3000 भारतीय छात्र हैं, जो मुख्य रूप से मेडिकल की पढ़ाई के लिए ईरान में रह रहे हैं। मौजूदा हालात को देखते हुए भारत सरकार ने अपने नागरिकों को ईरान की यात्रा से फिलहाल बचने की सलाह भी जारी की हुई है।

भारतीय छात्रों का रजिस्ट्रेशन हुआ पुरा

जम्मू और कश्मीर स्टूडेंट्स एसोसिएशन ने एक बयान जारी करते हुए बताया है, कि ईरान में मौजूद सभी भारतीय छात्रों का रजिस्ट्रेशन पूरा हो चुका है। भारतीय दूतावास ने छात्रों की व्यक्तिगत जानकारी और पासपोर्ट एकत्र कर लिए हैं। छात्रों के पहले बैच को रवानगी के लिए शुक्रवार सुबह 8 बजे तक तैयार रहने के निर्देश दिए गए। पहले बैच में गोलेस्तान यूनिवर्सिटी, शाहिद बहेश्ती यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज और तेहरान यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज के छात्र शामिल होंगे।

नागरिकों से मंत्रालय की अपील

विदेश मंत्रालय की ओर से जारी एडवाइजरी में ईरान में मौजूद सभी भारतीय नागरिकों से अपील की गई है कि वे अपने पासपोर्ट, वीजा और अन्य जरूरी दस्तावेज हमेशा अपने पास रखें और किसी भी आपात स्थिति में भारतीय दूतावास से तुरंत संपर्क करें। मंत्रालय ने साफ किया है कि सरकार स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए है और जरूरत पड़ने पर अतिरिक्त उड़ानों की व्यवस्था की जाएगी। भारतीय दूतावास, तेहरान ने सहायता के लिए आपातकालीन हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए हैं। नागरिक इन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं- 989128109115, 989128109109, 989128109102 और 989932179359। इसके अलावा बताए गए ईमेल के जरिए भी मदद ली जा सकती है।

दूतावास ने यह भी अपील की है कि जो भारतीय नागरिक अभी तक पंजीकरण नहीं करा पाए हैं, वे तुरंत एमईए की वेबसाइट पर उपलब्ध लिंक के जरिए रजिस्ट्रेशन कराएं। यदि इंटरनेट सेवाएं बाधित होने के कारण ईरान में मौजूद नागरिक पंजीकरण नहीं कर पा रहे हैं, तो भारत में उनके परिवार के सदस्य उनकी ओर से रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। इसी के साथ ही केंद्र सरकार ने भरोसा दिलाया है कि 'ऑपरेशन स्वदेश' के तहत हर भारतीय की सुरक्षित वापसी सुनिश्चित की जाएगी।

बीजेपी और चुनाव आयोग के कर्मचारियों के बीच बैठक क्यों? अभी आचार संहिता लागू है

-शिवसेना (यूबीटी) सांसद राउत के बयान से मुंबई के राजनीतिक हलकों में हलचल

मुंबई (एजेंसी)। शिवसेना (यूबीटी) सांसद संजय राउत के बयान ने मुंबई के राजनीतिक हलकों में हलचल मचा दी है। राउत ने बीएमसी चुनावों की पारदर्शिता पर गंभीर सवाल उठाए हैं। बृहन्मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) के चुनाव परिणामों के बीच जब शुरुआती रुझानों में बीजेपी समर्थित महायुति को बड़ी बढ़त मिलती दिखी, तब राउत ने मीडिया से बात करते हुए वोटिंग पैटर्न और वोटर लिस्ट को लेकर सत्तापक्ष पर तीखा हमला बोला।

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक राउत ने शुक्रवार को कहा कि उनकी पार्टी ने लोगों को भरोसा दिलाया है कि वे डरें नहीं, क्योंकि बीजेपी के नेतृत्व वाले महायुति ने बीएमसी चुनावों में बड़ी बढ़त हासिल कर ली है। उन्होंने कहा कि मुंबई जैसे शहर में जो वोटिंग पैटर्न चल रहा है, वह एक गंभीर मामला है। उन्होंने कहा कि हजारों लोगों के नाम, जिन्होंने विधानसभा चुनावों में भी वोट दिया था, उन इलाकों से गायब हैं जहां शिवसेना (यूबीटी), मनसे या कांग्रेस हैं। ईवीएम मशीन ठीक से काम नहीं करती...चुनाव आयोग हमारी बात सुनने को तैयार नहीं है। कल, बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं और चुनाव आयोग के कर्मचारियों के बीच एक बैठक हुई, क्यों? आचार संहिता अभी भी लागू है।

उन्होंने कहा कि वोटिंग प्रतिशत आने से पहले ही एग्जिट पोल आ गए...बीजेपी ने अपनी जीत का जश्न मनाना शुरू कर दिया...हमने लोगों को भरोसा दिलाया है कि वे डरें नहीं...। मतगणना से मिल रहे शुरुआती रुझानों के मुताबिबक बीजेपी-शिवसेना महायुति गठबंधन लगभग 52 वार्डों में आगे चल रहा है, यह शुरुआती डेटा पोस्टल बैलेट की गिनती से मिल रहा है। एसईसी और बीएमसी के आधिकारिक आंकड़ों का इंतजार है। अब तक गिने गए पोस्टल बैलेट के मुताबिक बीजेपी 35 सीटों पर, शिवसेना 17 सीटों पर आगे है।

वहीं ठाकरे भाइयों के लिए अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि शिवसेना (यूबीटी) 22 सीटों पर आगे बताई जा रही है। राज ठाकरे के नेतृत्व वाली महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) अब तक 8 सीटों पर आगे है। शुरुआती गिनती में कांग्रेस 4 सीटों पर आगे थी। राज्य चुनाव आयुक्त दिनेश वाघमारे ने वोटिंग खत्म होने के बाद कहा था कि 29 नगर निगमों में लगभग 50 प्रतिशत वोटिंग हुई। अधिकारियों ने शुक्रवार को बताया कि मुंबई नगर निगम चुनावों में 52.94 प्रतिशत वोटिंग हुई, जो 2017 के पिछले चुनावों में 55.53 प्रतिशत से कम है।

बता दें बीएमसी जिसका सालाना बजट 74,400 करोड़ रुपए से ज्यादा है, उसमें चार साल की देरी के बाद हो रहे चुनावों में 227 सीटों के लिए 1,700 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। मुंबई को छोड़कर, बाकी शहरी निकायों में मल्टी-मेंबर वार्ड हैं। ये 2022 में शिवसेना में फूट के बाद पहले बीएमसी चुनाव थे, जब अब उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पार्टी के ज्यादातर विधायकों के साथ अलग हो गए और बीजेपी के साथ गठबंधन करके मुख्यमंत्री बने थे।

उत्तर भारत में ठंड-कोहरे का डबल अटैक! शीतलहर से भी अभी नहीं मिलेगी राहत

नई दिल्ली (एजेंसी)। उत्तर भारत सहित देश के कई राज्यों में कड़ाके की ठंड ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, पश्चिम उत्तर प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड और ओडिशा में अगले दो दिनों तक शीतलहर की स्थिति बनी रहेगी। इसके बाद ठंड का असर धीरे-धीरे कम होने की संभावना है।

मौसम विज्ञान विभाग ने यह भी चेतावनी दी है कि उत्तर-पश्चिम भारत और बिहार में अगले पांच दिनों तक सुबह और रात के समय घना से बहुत घना कोहरा छाया रहेगा। कोहरे के कारण दृश्यता बेहद कम हो सकती है, जिसका सीधा असर सड़क, रेल और हवाई यातायात पर पड़ेगा। सड़कों पर वाहनों की रफ्तार थम सकती है, वहीं कई ट्रेनों के देरी से चलने की आशंका भी जताई गई है। मौसम विभाग के मुताबिक, पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ के कुछ इलाकों में अगले दो दिनों तक कोल्ड डे की स्थिति बनी रह सकती है। 16 और 17 जनवरी को हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और ओडिशा के अलग-अलग हिस्सों में शीतलहर का दौर जारी रहेगा। वहीं, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और झारखंड में भी 16 जनवरी को ठंड का प्रकोप देखने को मिल सकता है। मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और उत्तराखंड में 17 जनवरी तक घना से बहुत घना कोहरा छाए रहने की संभावना है। इसके बाद 22 जनवरी तक पंजाब-हरियाणा-चंडीगढ़ और 20 जनवरी तक उत्तराखंड के अलग-अलग इलाकों में घना कोहरा बना रह सकता है। पश्चिम उत्तर प्रदेश में 18 जनवरी तक और पूर्वी उत्तर प्रदेश में 19 जनवरी तक कोहरे का असर रहेगा।

मनरेगा के बाद अब शिक्षा और खाद्य सुरक्षा कानून में बदलाव की तैयारी में जुटा केंद्र

-यूपीए सरकार के दो बड़े अधिकार कानूनों पर मोदी सरकार की नजर

नई दिल्ली (एजेंसी)। मोदी सरकार यूपीए सरकार के दौर में बने दो बड़े सामाजिक अधिकार कानूनों-शिक्षा का अधिकार (आरटीई) और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून में बदलाव की तैयारी में जुटी है। मनरेगा की जगह नया कानून लाने के बाद अब केंद्र का फोकस इन योजनाओं की प्रभावशीलता बढ़ाने और लाभ सही लोगों तक पहुंचाने पर है। सरकार का मानना है कि केवल किसी योजना को कानूनी अधिकार बना देना पर्याप्त नहीं है, बल्कि उसका ज़मीन पर सही तरीके से लागू होना भी उतना ही जरूरी है।

केंद्र सरकार से जुड़े सूत्रों का हवाला देते हुए मीडिया रिपोर्ट में बताया गया है, कि शुरुआती तौर पर नियमों और प्रशासनिक आदेशों के जरिए सुधार करने की कोशिश की जाएगी। यदि इससे अपेक्षित नतीजे नहीं मिले, तो संसद में संशोधन या नया विधेयक लाने से भी इनकार नहीं किया गया है। इसके साथ ही सरकार इस बात पर भी विचार कर रही है कि आवास के अधिकार को भी कानूनी दर्जा दिया जाए। परामर्श प्रक्रिया से जुड़े एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि मनमोहन सिंह सरकार के समय बनाए गए विकास से जुड़े अधिकार कानूनों में तीन बड़ी कमियां सामने आई हैं। पहली, इन कानूनों के बावजूद हर बच्चे तक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं पहुंच पाई। दूसरी, खाद्य सुरक्षा का लाभ सभी पात्र परिवारों तक नहीं पहुंच सका। और तीसरी, लाभार्थियों की पहचान और पंजीकरण की प्रक्रिया अधूरी रही।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि सभी योजनाओं में 100 प्रतिशत लाभार्थियों का पंजीकरण सुनिश्चित किया जाए। सरकार चाहती है कि योजनाओं का लाभ सही व्यक्ति तक, सही समय पर और पारदर्शी तरीके से पहुंचे। इसी सोच के तहत संसद के शीतकालीन सत्र में मनरेगा की जगह 'विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन (ग्रामीण)' यानी वीबी- जी राम जी बिल पास किया गया था, जिसे दिसंबर 2025 में राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद कानून का दर्जा मिला।

सरकार अब शिक्षा, खाद्य सुरक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य और आवास, इन पांच अहम क्षेत्रों को लेकर तीन प्रमुख लक्ष्यों पर आगे बढ़ रही है। पहला, योजनाओं की पूरी कवरेज के लिए समय-सीमा तय की जाए। दूसरा, डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए रियल टाइम मॉनिटरिंग सुनिश्चित हो। तीसरा, हर लाभार्थी की पहचान और पंजीकरण के लिए राष्ट्रव्यापी अभियान चलाया जाए।

हालांकि, मनरेगा की जगह लाए गए नए कानून को लेकर विपक्ष ने कड़ा विरोध किया था। विपक्षी दलों का कहना है कि महात्मा गांधी का नाम हटाना केवल प्रतीकात्मक नहीं, बल्कि सामाजिक सोच पर असर डालने वाला कदम है। इसके बावजूद सरकार अपने एजेंडे पर आगे बढ़ती दिख रही है और अब शिक्षा व खाद्य सुरक्षा कानूनों में सुधार की दिशा में कदम तेज हो गए हैं।